Pharmaceutical Industry

भारत में औषधि उद्योग आयुर्वेद चिकित्सा के रूप में प्राचीन काल में अत्यंत समृद्ध था परन्तु विदेशी आक्रमणकारियों एवं ब्रिटिश हुकूमत के काल में भारतीय चिकित्सा उद्योग हतोत्साहित हुआ अतः Pharmaceutical ind. का विकास मूलतः स्वतंत्र भारत की देन है। ब्रिटिश काल में अधिकांश दवाओं का आयात किया जाता था।

वर्तमान में औषधि उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपनी घरेलू मांग का 95% स्वयं द्वारा उत्पादित दवाओं से पूर्ण किया है। केवल उच्च प्रौद्योगिकी युक्त औषधियों का ही आयात किया जाता है। ~~इस~~

इस समय देश में लगभग 250 औषधि इकाइयाँ (संगठित क्षेत्र) कार्यरत हैं।

5 → सार्वजनिक क्षेत्र
7 → संयुक्त क्षेत्र
500 → लघु इकाइयाँ स्थापित हैं।

100 से अधिक इकाइयाँ थोक दवाओं का निर्माण करती है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के Antibiotics, Vitamins, Penicillin, Harmones एवं जैव उत्पाद का उत्पादन होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रम

Indian drugs & Pharmaceutical Ltd – स्थापना 1961 में
इसके 5 संयंत्र ऋषिकेश, गुडगांव, चेन्नई, हैदराबाद एवं बिहार [illegible]
इसके 2 संयुक्त उपक्रम भी हैं –

1. ~~उक्त~~ Jaipur में Rajasthan drugs & Pharmaceutical Ltd.
2. Bhuvneshwar में Odisha drugs & Pharmaceutical Ltd.

Pharmaceutical Industry

भारत में औषधि उद्योग आयुर्वेद चिकित्सा के रूप में प्राचीन काल में अत्यंत समृद्ध था परन्तु विदेशी आक्रमणकारियों एवं ब्रिटिश हुकूमत के काल में भारतीय चिकित्सा उद्योग हतोत्साहित हुआ अतः Pharmaceutical ind. का विकास मूलतः स्वतंत्र भारत की देन है। ब्रिटिश काल में अधिकांश दवाओं का आयात किया जाता था।

वर्तमान में औषधि उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपनी घरेलू मांग का 95% स्वयं द्वारा उत्पादित दवाओं से पूर्ण किया है। केवल उच्च प्रौद्योगिकी युक्त औषधियों का ही आयात किया जाता है। ~~इस~~

इस समय देश में लगभग 250 औषधि इकाइयाँ (संगठित क्षेत्र) कार्यरत है।

5 → सार्वजनिक क्षेत्र
7 → संयुक्त क्षेत्र
500 → लघु इकाइयाँ स्थापित है।

100 से अधिक इकाइयाँ थोक दवाओं का निर्माण करती है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के Antibiotics, Vitamins, Penicillin, Harmones एवं जैव उत्पाद का उत्पादन होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रम

Indian drugs & Pharmaceutical Ltd – स्थापना 1961 में
इसके 5 संयंत्र
ऋषिकेश, गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद एवं बिहार में [illegible]
इसके 2 संयुक्त उपक्रम भी है –

(1) Jaipur में Rajasthan drugs & Pharmaceutical Ltd.
(2) Bhubaneshwar में Odisha drugs & Pharmaceutical Ltd.

Pharmaceutical Industry

भारत में औषधि उद्योग आयुर्वेद चिकित्सा के रूप में प्राचीन काल में अत्यंत समृद्ध था परन्तु विदेशी आक्रमणकारियों एवं ब्रिटिश हुकूमत के काल में भारतीय चिकित्सा उद्योग हतोत्साहित हुआ अतः Pharmaceutical ind. का विकास मूलतः स्वतंत्र भारत की देन है। ब्रिटिश काल में अधिकांश दवाओं का आयात किया जाता है था।

वर्तमान में औषधि उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपनी घरेलू मांग का 95% स्वयं द्वारा उत्पादित दवाओं से पूर्ण किया है। केवल उच्च प्रौद्योगिकी युक्त औषधियों का ही आयात किया जाता है। ~~इस~~

इस समय देश में लगभग 250 औषधि इकाइयाँ (संगठित क्षेत्र) कार्यरत है।

5 → सार्वजनिक क्षेत्र
7 → संयुक्त क्षेत्र
500 → लघु इकाइयाँ स्थापित है।

100 से अधिक इकाइयाँ थोक दवाओं का निर्माण करती है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के Antibiotics, Vitamins, Penicillin, Harmones एवं जैव उत्पाद का उत्पादन होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रम

Indian drugs & Pharmaceutical Ltd – स्थापना 1961 में
इसके 5 संयंत्र
ऋषिकेश, गुडगांव, चेन्नई, हैदराबाद एवं बिहार के [illegible]
इसके 2 संयुक्त उपक्रम भी है –

1. Jaipur में Rajasthan drugs & Pharmaceutical Ltd.
2. Bhubaneshwar में Odisha drugs & Pharmaceutical Ltd.

Hindustan Antibiotics ltd (HAR) :- स्थापना 1954 पुणे के पिंपरी नामक स्थान में जिसकी 3 सहायक इकाइयाँ राज्य सरकार के सहयोग से

① Karnataka Antibiotics & Pharmaceutical ltd, Bengaluru

② Maharastra Antibiotics & ~~Pharmaceutical~~ ltd, Nagpur

③ Manipur drugs & Pharmaceutical ltd - Imphal.

यह इकाइयाँ Penicillin समूह की दवाइयों का उत्पादन करता है।

Bengal chemical & Pharmaceutical ltd :- स्थापना - 1981 है इसकी 4 इकाइयाँ

① Kolkata के निकट ~~मि~~ मणिकतल्ला

② उत्तरी परगना जिले में ~~पानीघाटी~~ पानीहाटी

③ मुंबई

④ Kanpur

इसके अलावा ④ Bengal immunity ltd एवं smith Pharmaceutical ltd को दीवालियाँ घोषित कर बंद कर दिया गया है।

अन्य उत्पादक नगर - delhi, Kolkata, Mumbai, Bengaluru, Ahmadabad etc

समस्यायें :- ① इनमें प्रयुक्त कच्चे माल की बढ़ती कीमत एवं बढ़ती उत्पादक लागत

② पुरानी तकनीक एवं पुरानी मशीनें।

③ परंपरागत औषधि उद्योग का निरंतर ह्रास

④ लचीला Patent कानून

⑤ नकली दवाइयों की बाजार में उपलब्धता

⑥ समुचित R & d का अभाव।

संभावनायें :- ① बड़ा बाजार

② सस्ता एवं कुशल श्रमिक

③ सापेक्षिक उत्पादन लागत कम

④ गरीबी जिसके कारण अधिकांश लोगों तक दवाइयों की पहुँच नहीं।

Generics
- → आमें
- → आर्थिक
  - P ↓ Bislary. Xerox Godrej
  - P → X %, → Y %, → Z % } → Composition change

व्यवस्था अच्छी हो →

Cottage Industry

ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें केवल एक परिवार के सदस्य साधारण कच्चे माल एवं सामान्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर वस्तु उत्पादित करते है उन्हे कुटीर उद्योगों के अंतर्गत रखा जाता है। इन इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तु का विक्रय सामान्यत: उत्पादकों द्वारा ही उपभोक्ताओं को किया जाता है परन्तु वर्तमान में कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग वैश्विक स्तर पर बढने से निर्यात में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखता है।

भारत में कुटीर उद्योग प्राचीन काल से ही परम्परागत उद्योग के रूप में प्रचलित रहा है जो कालान्तर में वंशानुगत हो गया। यह उद्योग संपूर्ण भारत में पृथक-2 रूपों में व्याप्त है।

Ex- कर्नाटक एवं कश्मीर का काष्ठ शिल्प
झारखण्ड एवं MP का लाख उद्योग
बिहार, कर्नाटक एवं असम का रेशम कीट पालन उद्योग
एवं केरला का coire उद्योग

इसके अलावा बीड़ी एवं खेल का सामान संबंधी उद्योग संपूर्ण भारत में व्याप्त है।

औपनिवेशिक काल में इस उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप कुटीर उद्योग हतोत्साहित ही नही हुआ बल्कि नष्ट हो गया परन्तु स्वतंत्रता पश्चात योजनाओं के काल में कुटीर उद्योग हेतु अनेक प्रावधान किये गये।

Ex- 1956 की औद्योगिक नीति में कुटीर उद्योग हेतु सूची C आरक्षित बनाई गई तथा 6th FYP में इनके संरक्षण एवं वित्तीयन हेतु कई प्रावधान किये गये परन्तु नई आर्थिक नीति 1991 में liberalisation एवं Globalisation ने इस उद्योग को अत्यंत प्रोत्साहित किया।

भारत में कृषि का स्वरूप → आवश्यकता ? → संरचनागत
→ संस्थागत

कृषि के संरचनागत एवं संस्थागत कारक :-

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ आज भी लगभग 55% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है तथा GDP में लगभग 14% का योगदान है। परन्तु चिंता का विषय यह है कि भारतीय कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई है जिसका कारण कृषि में प्रयुक्त घातकों (Factors) की दयनीय दशा एवं कृषि की परंपरागत तकनीकि है।

कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों को हम निम्न वर्गों में रख सकते है।-

a) प्राकृतिक कारक :- मृदा, उच्चावच, जलवायु

b) संरचनागत कारक :- सिंचाई, बीज, उर्वरक, बिजली etc

c) संस्थागत कारक :- भूमि सुधार, बैंकिंग एवं वित्त की उपलब्धता
सरकारी प्रयास etc.

सिंचाई :- कृत्रिम रुप से जल को खेतों तक पहुँचाने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई कृषि कार्य हेतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण कारक है। इसके बिना उपयुक्त कृषि कार्य असंभव है। भारत में सिंचाई की महत्ता को निम्न बातों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

a) वर्षा की स्थानिक एवं कालिक विविधता

b) वर्षा की अनियमितता + Monsoon gap.

c) वर्षा की सीमित अवधि - 100 दिवसीय

d) फसलों का विशिष्ट स्वरूप -

चावल, जूट, गन्ना एवं खरीफ फसल → वर्षा ↑

गेहूँ, चना, दलहन, जौ (रबी फसल) → वर्षा ↓

भारत में कृषि का स्वरूप → आवश्यकता ? → संरचनागत
→ संस्थागत

कृषि के संरचनागत एवं संस्थागत कारक :-

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ आज भी लगभग 55% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है तथा GDP में लगभग 14% का योगदान है। परन्तु चिंता का विषय यह है कि भारतीय कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई है जिसका कारण कृषि में प्रयुक्त आगतों (Factors) की दयनीय दशा एवं कृषि की परंपरागत तकनीकि है।

कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों को हम निम्न वर्गों में रख सकते हैं :-

a) प्राकृतिक कारक :- मृदा, उच्चावच, जलवायु

b) संरचनागत कारक :- सिंचाई, बीज, उर्वरक, बिजली etc

c) संस्थागत कारक :- भूमि सुधार, बैंकिंग एवं वित्त की उपलब्धता, सरकारी प्रयास etc.

<u>सिंचाई</u> :- कृत्रिम रूप से जल को खेतों तक पहुँचाने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई कृषि कार्य हेतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण कारक है। इसके बिना उपयुक्त कृषि कार्य असंभव है। भारत में सिंचाई की महत्ता को निम्न बातों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

a) वर्षा की स्थानिक एवं कालिक विविधता

b) वर्षा की अनियमितता + Monsoon gap.

c) वर्षा की सीमित अवधि - 100 दिवसीय

d) फसलों का विशिष्ट स्वरूप -

चावल, जूट, गन्ना एवं खरीफ फसल → वर्षा ↑

गेहूँ, चना, दलहन, जौ (रबी फसल) → वर्षा ↓

e> वर्तमान में परती एवं बंजर भूमि के प्रयोग की नवीन प्रवृत्ति।

f> सूखे की समस्या को कम करने हेतु।

g> हरित क्रांति में प्रयुक्त फसलों की सफलता हेतु।

h> सिंचाई हेतु भौगोलिक दशा -

सिंचाई के विभिन्न साधन

स्रोत :- भारत भौगोलिक विविधताओं वाला देश है अतः सिंचाई के साधनों में भी विविधता पायी जाती है। Ex - ① कूप एवं नलकूप सिंचाई

② नहर सिंचाई

③ तालाब सिंचाई ---

④ अन्य साधन

कूप एवं नलकूप सिंचाई :- इस सिंचाई हेतु आदर्श दशायें वहां पर उपलब्ध होती है जहां भूमिगत जल की प्रचुरता एवं सतह के नजदीक उपलब्धता होती है। इसके साथ ही उर्वर मृदा क्षेत्रों में कूप सिंचाई का अधिक प्रचलन होगा क्योंकि कूप में लगा खर्च आसानी से निकल आता है।

कूप के प्रकार :-

(i) कच्चे कुएँ - 3-5 m गहरा, -कालिक,

(ii) पक्के कुएँ → साधारण कुआँ
→ नलकूप

कूप सिंचाई से लाभ :- a> सापेक्षिक लागत कम होती है अतः गरीब एवं निर्धन किसान भी उपयोग करते है।

b> खुदाई की प्रक्रिया अत्यंत सरल

c> कुएँ पर स्वामित्व एवं नियंत्रण किसान का अतः विवाद मुक्त।

d> सर्वसुलभ स्थानों पर

e) कुछ खनिज तत्त्व ex- Nitrate, Sulphate, Chloride etc. भूमिगत जल से प्राप्त हो जाते हैं अतः उर्वरता वृद्धि में सहायक है।

f) पर्यावरणीय समस्याओं से रहित ex - लवणीयता एवं क्षारीयता

कूप सिंचाई में निहित समस्यायें :- ① भूमिगत जल का उत्तरोत्तर घटता जाना

② सीमित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाना

③ सूखा काल में कूप का जल कम हो जाना अथवा सूख जाना

④ कई स्थानों से (जहां खारा जल है) खारा जल सतह पर आ जाता है।

वितरण :- UP, Punjab, Haryana एवं Bihar के अंतर्गत कुल भारत का 50% आता है। निरपेक्ष % के आधार पर गुजरात ≈ 75%, महाराष्ट्र ≈ 60%, राजस्थान ≈ 50%, UP ≈ 24% दक्षिण भारतीय राज्य - TN, Karnataka, Kerala, AP अपनी कुल सिंचाई का 10% से भी कम।

~~नहरी सिंचाई~~ :-

निरपेक्ष %
केवल गुजरात में
कूप
नहर
अलग-2

नहरी सिंचाई :- भारत में यह सिंचाई का महत्त्वपूर्ण साधन है। भारत में नहरी सिंचाई का कुल सिंचाई का लगभग 25% स्थान है। नहरों का सर्वाधिक विकास भारत के महान मैदानी क्षेत्रों में हुआ है जिसके लिए निम्न कारक जिम्मेदार हैं।

① सततवाहिनी / सदानीरा नदियों की उपलब्धता।

② भूमि का समतल स्वभाव

③ जलोढ मृदा में खुदाई में आसानी।

④ पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण अनिश्चितता

नहरों के प्रकार :-

a) नित्यवाही / सततवाही नहरें।

b) अनित्यवाही / बर्षाती नहरें

c) Storage work Canal → पहाडी क्षेत्र में बांध बनाकर जल store करके नहरों के माध्यम से प्रवाहित करना।

वितरण :- from Notes with Map.

नहरी सिंचाई से लाभ :- ① अधिकांश नहरें बारहमासी है। अतः कृषकों को हर समय जल की उपलब्धता, जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि।

Ex - Punjab, Haryana, W. UP की नहरें।

② बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण में सहायक।

③ जल परिवहन एवं विद्युत ऊर्जा उत्पादन में सहायक।

④ नहरी सिंचाई में नदियों की गाद की उपलब्धता खेतों तक पहुँचकर उर्वरता वृद्धि करती है।

नहरी सिंचाई से हानि :- ① जलाक्रांत एवं जलभराव की समस्या।
② लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या।

③ दलदली क्षेत्र से उत्पन्न विभिन्न कीटो एवं मच्छरों जनित उत्पन्न बीमारियाँ।

④ जल का अपव्यय अधिक

⑤ नहरों के टूटने से जान - माल की हानि

⑥ केवल समतल भूमि पर ही संभव।

⑦ निर्माण कार्य अत्याधिक लागत पूर्ण

Tank Irrigation (तालाब सिंचाई)

तालाब :- तालाब से आशय इन गढ्ढों से है जहाँ वर्षा का जल भर जाता है (अत्यंत छोटे नहीं)। यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूपों में होते है। कृत्रिम तालाब कच्चे एवं पक्के स्वरुप से होते है। इनका आकार छोटे पोखर (Pond) से लेकर बडी झीलों तक हो सकता है।

तालाब हेतु आदर्श दशायें :- ① सतह पर प्राचीन कठोर अप्रवेश्य एवं अरन्ध्र युक्त चट्टानी संरचना।

② वर्षा जल की उपलब्धता।

③ भारत में तालाब हेतु आदर्श दशायें प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पायी जाती है जिसका कारण नि.लि. है।

a) प्राचीन कठोर, अप्रवेश्य, अरन्ध्र युक्त चट्टानी संरचना
b) वर्षा जल की उपलब्धता।
c) सिंचाई के अन्य स्रोतो की अनुपलब्धता
d) सदानीरा नदियों की अनुपस्थिति।
e) रोजगार हेतु मत्स्यन।

लाभ :- ① वर्षा जल का उपयोग
② पठारी क्षेत्र में उपलब्ध उपयुक्त कारक
③ इन पर स्वामित्व एवं नियंत्रण निजी व्यक्तियों का होता

a) जल संरक्षण को बढावा
b) विवाद मुक्त
c) मत्स्यन को बढावा

हानि / समस्यायें :- ① वर्षा पर निर्भरता अतः सूखा काल में तालाब सूख जाते है।

② तालाब में गाद जमाव की समस्या।

③ वाष्पीकरण की समस्या।

④ सीमित क्षेत्र में सिंचाई।

⑤ तालाब निर्माण हेतु अधिक भूमि की आवश्यकता।

⑥ कृत्रिम तालाब निर्माण हेतु अधिक पूँजी की आवश्यकता।

सिंचाई के अन्य साधन :-

बहुउद्देश्यीय योजनाओं द्वारा प्राप्त सिंचाई की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। बहुउद्देश्यीय परियोजना से तात्पर्य नदी घाटी में उपलब्ध सभी उपयोगी सुविधाओं अथवा संसाधनों का ~~पूर्ण~~ रूपेण उपयोग करना है। ∵ इनका उपयोग बहुउद्देश्यीय है अतः इन्हें बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा -

a> सिंचाई कार्य

b) बाढ़ नियंत्रण

c> मृदा क्षरण पर रोक

d> मत्स्यन

e) पेयजल

f> परिवहन एवं पर्यटन का विकास

g> जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन

सिंचाई की विभिन्न प्रणालियाँ :-

i) बाढ़ / प्रवाह कृषि (flood irri)

ii) छिड़काव सिंचाई (sprinkler)

iii) टपकन सिंचाई (Drip irri)

बीज (Seed) :- बीज कृषि विकास अर्थात् उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्ति हेतु भारत ने पश्चिमी देशों के कृषि model की विशेषताओं को अपनाया जहां पर बीजों की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।

भारत में बीजों का गुणवर्धन / बहुगुणन के लिए निम्न 3 चरणों का प्रयोग किया जाता है।

1) Breeder-seeds (प्रजनक बीज)
2) Foundation seed (आधार बीज)
3) certified seed (प्रमाणित बीज)

प्रजनक बीज :- यह मौलिक बीज है जो कि उत्तम गुणवत्ता हेतु प्राकृतिक रूप से खोजा गया है।

आधार बीज - कृषि संस्थाओं द्वारा प्रजनक बीजों से उत्पन्न

प्रमाणित बीज :- आधार बीजों से उत्तम खेत, आवश्यक उर्वरक फसल निरीक्षण, उचित भण्डारण जिसमें नमी etc की मात्रा संतुलित की सुविधा से संपन्न बीज का उत्पादन

धान → करधना
धान → डेहुला

उन्नत बीज के गुण :- ①. उर्वरकों के उपयोग में अनुकूलता
② वर्धन काल एवं पकने की अवधि कम होनी चाहिए।
③ सिंचाई की अनुकूलता
④ कीट प्रतिरोधी

उन्नत बीजों के प्रयोग में कठिनाई :- ① उर्वरकों पर निर्भरता अधिक।

② सिंचाई हेतु जल अधिक।
③ कीटनाशकों का प्रयोग अधिक।
④ किसानों में व्याप्त गरीबी / क्रय शक्ति का अभाव
⑤ आधुनिक आगतों अर्थात मशीन भूमि सुधार etc का अभाव
⑥ तकनीकी ज्ञान का अभाव
⑦ लोगों की परंपरागत सोच
⑧ अन्य

उन्नत बीज कार्यक्रम की कमियाँ :- ① पूर्ण परीक्षण का अभाव- इन बीजों के प्रयोग से पर्यावरण तथा मानव पर क्या प्रभाव होगा इसका समुचित परीक्षण नहीं किया जाता। — Ex- Bt फसलों से उत्पन्न पर्यावरणीय एवं जैविक समस्याओं से देखा जाता है।

Bt- cotton ↓ बीज को ↓ भेड़ को खिलाया ↓ effect - Blood deficiency lung dise.

② चयनित फसलों के प्रति झुकाव। Ex- गेहूँ चावल के प्रति झुकाव किन्तु मोटे अनाज एवं दलहन की उपेक्षा

③ MNC's पर निर्भरता /
④ बाजार में उपलब्ध नकली बीजों से प्रतिस्पर्धा

GM seed Production in India ↓ Mosento ↓ US comp.

वर्तमान में लगभग 240 उद्योग क्षेत्र जिसमें लगभग 1.5 crore व्यक्तियों को रोजगार एवं लगभग 60,000 crore का व्यापार

भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान :- ① रोजगार सृजन
② PCI में वृद्धि

③ निर्धनता में कमी
④ राष्ट्रीय आय में वृद्धि
⑤ ग्रामीण विकास संतुलित विकास
⑥ उद्योगों का विकेन्द्रीकरण
⑦ निर्यातों में योगदान
⑧ सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं का
⑨ औद्योगिक विवादों से मुक्त
⑩ पर्यावरण अनुकूल

समस्यायें :- ① कच्चे माल की अपर्याप्तता एवं गुणवत्ता युक्त कच्चे माल की अनुपलब्धता

② ऊर्जा की अत्यंत कमी।
③ पुरानी मशीनें एवं पुरानी तकनीकें
④ वित्त का अभाव
⑤ तकनीकी सहायता का अभाव
⑥ विपणन / विक्रय की समस्या
⑦ आधुनिक वैश्विक बाजार से प्रतिस्पर्धा
⑧ आधुनिक मिलों से प्रतिस्पर्धा
⑨ निम्न गुणवत्ता

विकास की संभावना :- ① भारत का वृहद बाजार
② पर्यावरण अनुकूल

③ बढ़ती वैश्विक माँग
④ सहज उपलब्धता
⑤ सरकारी नीतियाँ एवं कुटीर उद्योग → Home work.

08/09/2012

कृषि

- अवसंरचना
- संस्थागत

यातायात — भूमि /जलवायु

बीज

पूँजी बाजार

उद्यमिता श्रम

~~यातायात~~ सिंचाई

R&D

कीटनाशक

उर्वरक

तकनीकि

राजनैतिक इच्छाशक्ति

मशीन

भण्डारण

ऊर्जा

बीमा योजना

उपयुक्त प्राकृतिक कारक
बीज
सिंचाई / उर्वरक / कीटनाशक
ऊर्जा / श्रम
तकनीक / मशीन
} → संरचनागत कारक

सिंचाई →
- क्या है
- आवश्यकता क्यों
- स्रोत
- आदर्श
- वितरण
- समस्या

उर्वरक :- उर्वरक फसल उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण पोषक तत्त्व हैं जो कि मृदा की उर्वरता में वृद्धि कर micronutrient की कमी को पूरा करते हैं। यह कृषि में प्रयुक्त ऐसे महत्त्वपूर्ण आगत हैं जो कि कृषि कार्य एवं उद्योगों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

Imp Biofertilizer लाभ

सामान्यतः भारतीय मृदा समूह में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्त्वों Ex- N_2, P, Potash एवं Humus etc की कमी पायी जाती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाते हैं।

Humus की मात्रा जलधारण क्षमता को बढ़ा देती है।

उर्वरकों से लाभ :- ① मृदा में पोषक तत्त्वों की वृद्धि करते हैं।
② मृदा जलधारण क्षमता में वृद्धि।
③ उर्वरक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। (Agrofuels
④ यह मृदा को — — —
⑤

उर्वरकों के प्रकार :- a) **रासायनिक उर्वरक** :- पौधों को इनकी आवश्यकता अधिक होती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण NPK है। एवं Ammonium sulphate, Potassium sulphate etc

लाभ :- ① उत्पादन में सहजता
② उपयोग सरल - - -
③ घुलनशीलता उच्च
④ मृदा में पोषण स्तर में तीव्र वृद्धि
⑤ परिवहन, रख-रखाव एवं प्रबंधन में आसानी

कमी :- ① असंतुलित प्रयोग से मृदा एवं पादप वर्ग दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव।
② जल खपत अधिक।
③ सरकार पर सब्सिडी बोझ
④ मूल्य अधिक।

b) जैव उर्वरक :- ① Compost खाद (Manure)
② Rhizobium
③ Blue-Green Algae
④ Azetobacter etc.
⑤ Vermi-compost

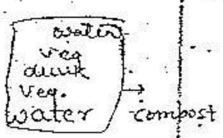

लाभ :- ① मृदा उत्पादकता एवं मृदा में जैव क्रियाशीलता को बढाते हैं।

② Nitrogen fixation में वृद्धि।

③ रासायनिक उर्वरक की तुलना में सस्ते।

④ पर्यावरण अनुकूल

⑤ ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्माण संभव

उर्वरक उपयोग / खपत प्रतिरूप

a) स्थानिक ~~अ~~ प्रतिरूप / विषमता → Haryana, Pun = 267 kg/hect
→ NE India → ↓

b) प्रायोगिक प्रतिरूप / विषमता → Urea का Use अधिक + C.F का use अधिक, BF का use कम

c) मौसमी प्रतिरूप / विषमता → खरीफ → ~~अ~~ कम use Fertiliser का
→ रबी → use अधिक

d) फसलगत प्रतिरूप / विषमता → दलहन, तिलहन में use कम
→ गन्ना गेहूँ चावल में अधिक use

औसत उर्वरक उपयोग India में = 145 kg/hect

उर्वरकों की समस्यायें :- ① पर्यावरणीय समस्या
② - सामाजिक समस्या
③ अंतर प्रादेशिक विषमता

↓ Haryana, Punjab, w. UP → उर्वरकों का प्रयोग किया

↓ MP, Bihar, Orissa, → उपयोग नहीं किया

ऊर्जा (Power)

- भूमिका
- प्रकार
  - परंपरागत
  - गैर परंपरागत
- उपयोग → ग्रामीण कृषि विकास में गैर परंपरागत कैसे सहायक
- लाभ
- हानि / समस्यायें

03/09/2011

कृषि के संस्थागत कारक

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं विकास के लिए अपनायी जाने वाली विभिन्न युक्तियों में संरचनागत कारक के साथ-2 संस्थागत कारकों की अहम् भूमिका है। जहां संरचनागत कारक कृषि में भौतिक उन्नयन करते हैं वहीं संस्थागत कारक कृषकों में उद्यमिता हेतु प्रेरणा जागृत करते हैं। इसके अंतर्गत निम्न कारकों को देखा जा सकता है :

a) भूमि सुधार...
b) लगान का सरलीकरण
c) बैंकिंग व्यवस्था
d) तकनीकी (R.&d) + मशीनीकरण etc

भूमि सुधार :- भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि एवं श्रम के मध्य संबंध में आदर्शवादी समाजवादी परिवर्तन से है जो कि न्याय एवं समता के मूल पर आधारित है। भूमि सुधार एक मंद क्रांति का द्योतक है। इसके 4 नि. लि. प्रमुख उपागम हैं।

a) बिचौलियों की समाप्ति
b) कास्तकारी सुधार
c) भूमि की हदबंदी / सीमाबंदी
d) भूमि की चकबंदी

बिचौलियों की समाप्ति :- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियाँ प्रचलित थीं।

i) जमींदारी व्यवस्था → Orrissa, Bengal, Bihar
ii) महालबाड़ी व्यवस्था → Punjab, संयुक्त प्रान्त, Rajasthan
iii) रैयतबाड़ी व्यवस्था → असम, बंबई एवं मद्रास प्रेसीडेन्सी

इन तीनों व्यवस्थाओं में बिचौलिया वर्ग उपस्थित था अंतर केवल लगान के वसूल किये जाने के स्वरूप में था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही 2 वर्षों के अंदर अनेक प्रदेशों ने जमींदारी उन्मूलन हेतु कानून बनाये किन्तु सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर जमींदारी उन्मूलन कानून 1956 बना जिसे अधिकतर राज्यों ने स्वीकार कर लिया। विभिन्न राज्यों के बिचौलियों की समाप्ति हेतु बनाये गये कानूनों की विशेषतायें निम्न है :

① वन बंजर एवं परती भूमि को जमींदारों से छीनकर राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया।

② कई राज्यों ने घरेलू भूमि को छोड़कर पट्टे वाली भूमि कृषकों को आवंटित कर दिया साथ ही कुछ राज्यों ने घरेलू भूमि पर ही अपना अधिकार कर लिया।

EX- UP, MP, Delhi, अजमेर etc

एवं इसके क्षतिपूर्ति में उन्हें वित्त प्रदान कर दिया गया।

③ अधिकांश राज्यों ने कृषि भूमि पर कार्यरत पट्टेदार कृषकों को भूधारण / पूर्ण स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर दिया।

इन प्रयासों के बावजूद जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून में कई कमियां रह गयी जिसका लाभ बिचौलिया वर्ग ने उठाया और उन्होंने अपनी जमीन पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया।

पट्टे वाली भूमि — मौखिक / लिखित

22/23

- काश्तकारी सुधार :- काश्तकारी व्यवस्था से तात्पर्य कृषि की उस प्रणाली से है जिस पर भूमि का मालिक स्वयं उपयोग नहीं करता जमीन को काश्तकारों को पट्टे पर दे देता है। इस सुधार के अंतर्गत निम्न पक्ष आते है।

(1) 6 या 6 वर्ष से अधिक समय तक खेती की गई जमीन पर मालिकाना हक काश्तकारों को प्रदान हो जायेगा।

(2) काश्तकारों से लगान उचित स्तर पर लिया जायेगा।

(3) कुछ सीमाओं के साथ काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार मिलना।

काश्तकारों के बेदखली एवं बेदखली रोकने हेतु कानून बनाये गये परन्तु कानून में अस्पष्टता एवं विसंगतियों के कारण लाभ भूस्वामियों को ही मिला। काश्तकारों का पक्ष इस दृष्टिकोण से काफी कमजोर रहा कि काश्तकारी मौखिक थी और इन भू-रिकार्डों पर इनका उल्लेख नहीं किया गया था। इन कानूनों में 'काश्तकार', 'स्वैच्छिक काश्तकार', 'व्यक्तिगत कृषि' आदि परिभाषायें अस्पष्ट हैं।

भूमि सीमाबंदी :- इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि को जमींदारों से लेकर छोटे-2 किसानों में बांट दिया जाये लेकिन भूस्वामित्व की सीमा विभिन्न-2 कोटि की जमीनों के लिए अलग-2 निश्चित की गई।

Ex- सिंचित एवं उर्वर जमीन हेतु
वन, बंजर एवं परती जमीन हेतु पृथक-पृथक नियम

पृथक-पृथक राज्यों में हद बंदी से संबंधित अलग सीमा भी निर्धारित की गई।

Ex- WB → 27 एकड़
UP → 25 → 12 (वर्तमान)
AP → 30 - 57 एकड़
MP → 36 एकड़

सीमांकन संबंधी कानून दो चरणों में पारित हुआ

(1) 1956 - 72 तक

(2) 1972 के बाद

1972 तक सीमाबंदी की इकाई व्यक्ति को माना गया जबकि 72 के बाद सीमाबंदी की इकाई परिवार को माना गया लेकिन परिवार की संख्या के आधार पर इसे बढ़ाने व घटाने की छूट राज्य सरकारों को दी गई।

सीमांकन की समस्यायें :- (1) भूमि हदबंदी का गलत तरीके से स्थानांतरण ।

Ex - a) परिवारों के सभी सदस्यों के नाम भूमि हो गयी ।

b) बेनाम स्थानांतरण भी किया गया ।

(2) राज्यों द्वारा तय की गई हदबन्दी में काफी विषमता ।

Ex - Assam - 50 Acre

Punjab - 30 Acre

(3) परिवार की संख्या के आधार पर राज्यों को हदबन्दी बढ़ाने का अधिकार (5 व्यक्तियों से अधिक)

(4) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सुझाव था कि कुछ [illegible] हेतु भूमि को हदबंदी से अलग रखा जाये।

Ex - बागानी कृषि, दुग्ध उत्पादन फार्म etc / [illegible] व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देना था।

(5) कानून बनाने में की गई देरी

भूमि की चकबंदी :- चकबंदी से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कृषकों की बिखरी हुई जमीनों को आपसी समझौता के द्वारा एक स्थान पर करने का प्रयास किया जाता है।

भूमि की गुणवत्ता के आधार पर अधिक या कम भूमि की सीमा निर्धारित की जाती है।

स्पष्ट हो कि भारत में भू जोतों का आकार 1 hect / इससे भी कम है जो यत्र तत्र बिखरे हैं। यदि वैश्विक दृष्टि से देखा जाये तो US में 1 भूजोत का आकार 158 acre, Canada – 1,900 Acre, Argentina – 124 acre प्राप्त होता है। छोटी भू जोत में आधुनिक आगतों का समुचित प्रयोग करने में कठिनाई होती है।

भारत में छोटी भू जोत का कारण :- ① भारत में अत्याधिक जनसंख्या भार।

② भारत में उत्तराधिकार कानून

③ भारत में एकल परिवार के प्रति बढती आस्था

चकबन्दी के प्रकार :- ① ऐच्छिक चकबन्दी
② अनिवार्य चकबन्दी
→ Ex - पंजाब, गुजरात, MP, WB में लागू परन्तु पंजाब में काफी हद तक सफल,
→ इसके अंतर्गत कृषक को अनिवार्यत: चकबंदी करना होता है इसलिए इसे कानूनी चकबंदी भी कहा जाता है।

असम

उल्लेखनीय है कि NE India, TN में कोई चकबन्दी कानून नहीं है जबकि पंजाब एवं हरियाणा में चकबन्दी का कार्य पूर्ण कर लिया है।

चकबंदी की बाधायें :- ① भूमि के प्रति किसानों का लगाव
② भूमि के मूल्य में अंतर

③ चकबंदी से जुड़े कर्मचारियों का भ्रष्ट एवं अप्रशिक्षित होना ;

④ सरकार पर वित्त बोझ अधिक

चकबंदी से लाभ :- ① उत्पादन के साथ income एवं livin Standard में भी सुधार होता है।

② आधुनिक आगतों के प्रयोग हेतु समुचित जमीन उपलब्ध हो जाती है।

③ पूँजीगत साधनों का समुचित प्रयोग हो पाता है।

④ भूमि अपव्यय की कमी होती है। Ex- बड़ी जोत पर मेंड़ों का न होना।

⑤ आपसी विवाद की स्थिति कम हो जाती है।

भूमि सुधारों के अंतर्गत कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु इन सुधारों के अतिरिक्त सहकारी कृषि, भू अभिलेखों का लेखांकन को बढ़ावा दिया गया।

सहकारिता का गठन कृषि उत्पादकता में वृद्धि एवं लागत में कमी के उद्देश्य से किया जाता है जिससे छोटी भू जोतों से भी अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। सहकारिता से छोटे किसानों को भी वह लाभ प्राप्त होते है जो ~~छोटे~~ बड़े किसानों के पास होते है।

अन्य संस्थागत कारकों की भांति आपसी ईर्ष्या, अशिक्षा इत्यादि के कारण सहकारिता आंदोलन भी असफल रहा

स्पष्ट हो कि भारत में भू जोतों का आकार 1hect / इससे भी कम है जो यत्र तत्र बिखरे है। यदि वैश्विक दृष्टि से देखा जाये तो US में 1 भूजोत का आकार 158 acre, Canada – 1,300 Acre, Argentina – 124 acre प्राप्त होता है। छोटी भू जोत में आधुनिक आगतों का समुचित प्रयोग करने में कठिनाई होती है।

भारत में छोटी भू जोत का कारण :- ① भारत में अत्यधिक जनसंख्या भार।

② भारत में उत्तराधिकार कानून

③ भारत में एकल परिवार के प्रति बढती आस्था

चकबन्दी के प्रकार :- ① ऐच्छिक चकबन्दी

② अनिवार्य चकबन्दी

→ Ex. पंजाब, गुजरात, MP, WB में लागू परन्तु पंजाब में काफी हद तक सफल।

→ इसके अंतर्गत कृषक को अनिवार्यतः चकबंदी करना होता है इसलिए इसे कानूनी चकबंदी भी कहा जाता है।

असम

उल्लेखनीय है कि NE India, TN में कोई चकबन्दी कानून नहीं है जबकि पंजाब एवं हरियाणा में चकबन्दी का कार्य पूर्ण कर लिया है।

चकबंदी की बाधायें :- ① भूमि के प्रति किसानों का लगाव

② भूमि के मूल्य में अंतर

③ चकबंदी से जुडे कर्मचारियों का भ्रष्ट एवं अप्रशिक्षित होना।

④ सरकार पर वित्त बोझ अधिक

चकबंदी से लाभ :- (1) उत्पादन के साथ income एवं livin Standard में भी सुधार होता है।

(2) आधुनिक आगतों के प्रयोग हेतु समुचित जमीन उपलब्ध हो जाती है।

(3) पूँजीगत साधनों का समुचित प्रयोग हो पाता है।

(4) भूमि अपव्यय की कमी होती है। ex- बडी जोत पर मेंडों का न होना।

(5) आपसी विवाद की स्थिति कम हो जाती है।

भूमि सुधारों के अंतर्गत कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु इन सुधारो के अतिरिक्त सहकारी कृषि, भू अभिलेखों का लेखांकन को बढावा दिया गया।

सहकारिता का गठन कृषि उत्पादकता में वृद्धि एवं लागत में कमी के उद्देश्य से किया जाता है जिससे छोटी भू जोतो से भी अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। सहकारिता से छोटे किसानों को भी वह लाभ प्राप्त होते है जो ~~छोटे~~ बडे किसानों के पास होते है।

अन्य संस्थागत कारको की भांति आपसी ईर्ष्या, अशिक्षा इत्यादि के कारण सहकारिता आंदोलन भी असफल रहा

श्वेत क्रांति (Short Notes)

भूमिका — श्वेत क्रांति से आशय पूर्व में चले आ रहे दुग्ध उत्पादन की तुलना में आशातीत वृद्धि से है।

भारत ने 1951 में प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 124 gm/व्यक्ति/दिन थी जो कि 1970 में 112 gm प्राप्त हुई जिसका कारण तीव्र दर से बढती जनसंख्या थी। अतः इस बढती जनसंख्या में कुपोषण की विभीषिका को कम करने एवं प्रोटीन की उपलब्धता बढाने हेतु दुग्ध उत्पाद में तीव्र वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गई। परिणामतः 4th FYP में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में National dairy dev. Proj. (NDDP) चलाया गया। दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीस ने गुजरात के खेडा जिले में AMUL (Anand Milk Udyog Ltd) की स्थापना कर दुग्ध क्रांति की नींव रखी। दुग्ध क्रांति को ही श्वेत क्रांति (operation flood के नाम से जाना जाता है।

श्वेत क्रांति की सफलता हेतु operation flood चलाया गया जिसके तीन चरण है :-

i) 1970-80 :- इस चरण में भारत में तीव्र दर से बढती जनसंख्या, बढता नगरीकरण एवं दुग्ध उत्पादों की मांग को देखते हुए 17 Feeder dairy स्थापित की गई। आनन्द में AMUL की स्थापना के साथ-2 4 महानगरों में Mother dairy की स्थापना की गई।

इसके अतिरिक्त NDDP के अंतर्गत SDDP (State), DDDP (District), Block DDP चलाये गये। सहकारी समितियों का गठन, पंचायत स्तर पर सहकारिता का गठन किया गया। इस प्रकार ग्रामीण दुग्ध आपूर्ति को राज्य एवं केन्द्र स्तर से जोडा गया। उल्लेखनीय है कि operation flood गुजरात में सफल रहा जिसका कारण वहाँ की भौगोलिक दशाओं की अनुकूलता e.x विशाल चारागाह, उपयुक्त जलवायु, किसानों में दुग्ध उत्पाद व्यवसाय के प्रति उत्सुकता एवं सहकारी समितियों की स्थापना।

श्वेत क्रांति का प्रथम चरण सफल था क्योंकि 1980 में दुग्ध उत्पादकता 112 gm / व्यक्ति से बढ़कर 142/ व्यक्ति / दिन हो गयी।

② 1980 - 85:- 6th FYP में नगरीय मांग एवं प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के दृष्टिकोण से इस चरण का आरंभ किया गया। इस चरण में 144 नगरों में National milk grid के माध्यम से निर्यातोन्मुख व्यापार उत्पन्न किया गया तथा पशुओं हेतु उपयुक्त चारे की व्यवस्था, बीमारी की रोकथाम, आदि की व्यवस्था की गई।

इस चरण में दुग्ध क्रांति का विस्तार गुजरात के समीपी राज्यों Raj. MP, Maharastra, Karnatak के साथ-साथ TN में भी किया गया। परिणामतः दुग्ध उपलब्धता बढ़कर 179 gm / व्यक्ति / दिन हो गयी।

भारत में कुल दुग्ध उत्पादन 1970 में 46 m tonne था जो कि बढ़कर (140) m tonne हो गया दुग्ध उत्पादन में इस आशातीत वृद्धि को ही श्वेत क्रांति के नाम से संबोधित किया गया।

③ 1985 - 94 :- 7वीं एवं 8वीं FYP में इस श्वेत क्रांति का अग्रिम प्रयास देश के 22 राज्यों में 250 केन्द्रों की स्थापना करना था। इस चरण का विस्तार UP, Bihar, WB, Punjab etc. में किया गया।

Operation flood एक एकीकृत कार्यक्रम है। तृतीय चरण में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, नयी प्रजातियों का विकास एवं उनके लिए समुचित पोषक तत्वों की उपलब्धता पर जोर दिया गया जिससे भारत के Tea cup ωω की संकल्पना झूठी हो सके।

Operation flood एक एकीकृत कार्यक्रम है। जिसके अंतर्गत dairy समितियों के माध्यम

से लगभग 85 Lakh किसानों को लाभ पहुँचाया गया।
वर्तमान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 270 gm / व्यक्ति / दिन
हो गयी है एवं उत्पादन ... — हो गया है।
वर्तमान में भारत दुग्ध उत्पादों का निर्यात भी करने लगा है
तथा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है।

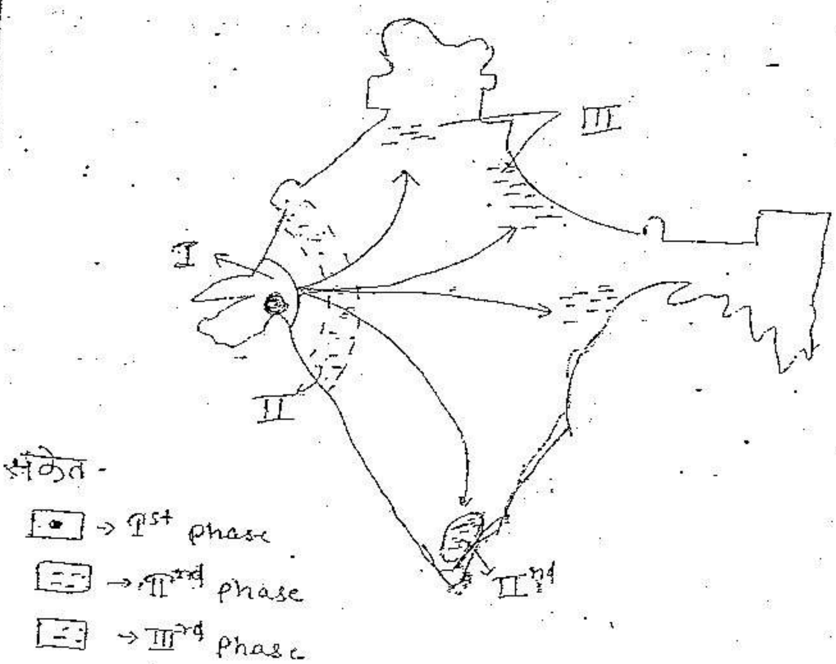

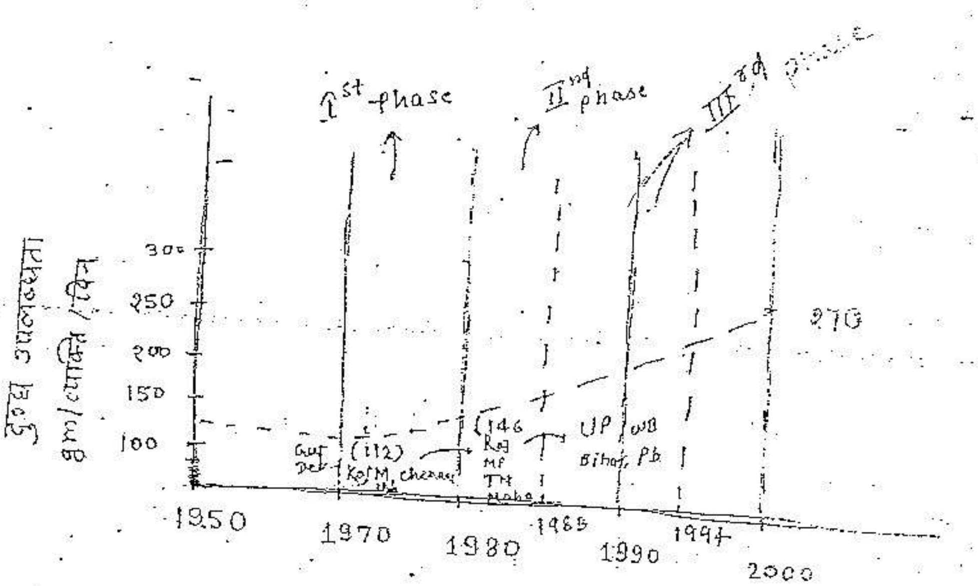

श्वेत क्रांति के विभिन्न उपागम :- ① सहकारी समितियों की स्थापना ।

② ग्रामीण अधिसंरचना का विकास जिसमें सड़क - बिजली एवं यातायात की समुचित उपलब्धता ।

③ ग्रामीण ऋण की समुचित उपलब्धता

④ नस्ल सुधार कार्यक्रम।

⑤ शोध एवं विकास कार्य

⑥ वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था ।

बाधायें :- ① दूर- दराज क्षेत्रों से दुग्ध एकत्रण ।

② नस्लों के सुधार में कमी ।

③ उत्तम नस्ल हेतु अस्वस्थ वातावरण

④ विपणन सुविधाओं का समुचित अभाव

⑤ पर्याप्त आधारभूत संरचना का अभाव

सरकारी प्रयास :-

16/09/2012
Morning

ग्रामीण अधिवास

अधिवासों के प्रकार, प्रतिरूप, आकारिकी
पर्यावरणीय समस्यायें

- परिभाषा
- नगरीय अधिवासों से पृथकता
- स्थापना के कारक
- रूप
- प्रकार — विधियाँ; प्रतिरूप

(रूप, प्रकार, विधियाँ, प्रतिरूप) } आकारिकी

परिभाषा :- ग्रामीण अधिवासों से तात्पर्य गृहो के समूह या भौतिक संरचना मात्र से न होकर परंपरागत रुढिवादी समाज से है जिसमें सामाजिक अंर्तमुखीयता, धार्मिक एवं सामाजिक केन्द्रीयता की प्रधानता होती है।

यहाँ गृहो की संरचना आकृति एवं समूहन पर भूमि की उर्वरता, भू-भौतिक दशाओं एवं जीवन के सांस्कृतिक पक्षो का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अधिवासों को नगरीय अधिवासों से पृथक करने हेतु UN ने नि.लि. 4 प्रतिमान दिये है।

a) जनांककीय प्रतिमान
b) प्रकार्यात्मक प्रतिमान / आर्थिक क्रियाओं से संबंधित
c) सामाजिक / सांस्कृतिक प्रतिमान
d) भौतिक आकारिकी संबंधित प्रतिमान

जनांकिकीय प्रतिमान :- जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व को निर्धारक माना जाता है। परन्तु यह प्रतिमान निरपेक्ष रूप से पूर्ण नहीं है।

Ex- भारत एवं आस्ट्रेलिया का जनसंख्या स्वरूप

प्रकार्यात्मक प्रतिमान :- इसके अंतर्गत ग्राम एवं नगरों की आर्थिक क्रियाओं को निर्धारक माना जाता है। गाँवों में प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता होती है, जबकि नगरों में द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की प्रधानता।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिमान : ग्रामीण अधिवासों का महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है। गावों में परंपरागत समाज, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास etc की प्रधानता परन्तु नगरों में आधुनिक विचारों की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है।

भौतिक आकारिकी प्रतिमान- इसके अंतर्गत ग्रामीण अधिवासों में सड़क एवं राजमार्गों की चौड़ाई परिवहन के साधन, बाजार की संरचना, आवासीय क्षेत्रों का समूहन आदि लिये जाते है जो कि नगरीय-अधिवास से पृथक करते हैं।

- भारत में जनसंख्या आयोग [illegible] 2 प्रतिमान स्थापित किये है।

(1) यदि कोई बस्ती प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा वैधानिक नगर के रूप में घोषित की गई हो।

Ex - छावनी क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र, नगरनिगम, नगरपालिका etc घोषित किया गया हो वह नगरीय अधिवास [illegible]

इन्हे वैधानिक नगर का दर्जा दिया जाता है।

(2) इसके अंतर्गत निम्न 3 प्रतिमान स्थापित होते है,

a) जनसंख्या घनत्व - 400 व्यक्ति / km^2

b) गैरकृषिकार्य में संलग्न जनसंख्या - 75% से कम न हो।

प्रभावित करने वाले कारक :- ① मृदा की संरचना।
② भूभौतिक संरचना।

(3) जल की उपलब्धता।

(4) सामाजिक सांस्कृतिक व धार्मिक परिवेश।
मानव की परंपरागत सोच

ग्रामीण अधिवास के रूप :- ग्रामीण अधिवासों के रूप से आशय गृहों की संख्या से है अर्थात गृह संख्या की अधिकता अथवा कमी के आधार पर नि. लि. 3 रूप स्थापित किये गये है

a) विलगित अधिवास (Farmsted settlement) :- विलगित अधिवासों में गृहों की संख्या 1 या 2 होती है। इस प्रकार का समूहन वैश्विक स्तर पर समशीतोष्ण घास भूमियों Ex- प्रेयरी पम्पास etc में तथा भारत में विषम भू भौतिक ~~संरचना~~ दशाओं वाले स्थानों पर।

Ex. पश्चिमी राजस्थान, कच्छ का क्षेत्र etc

b) पुर्वा अधिवास (Hamleted settlement) :- अधिवासों के इस रूप में गृहों की संख्या 3 से 9 तक होती है। इस प्रकार का अधिवास

पशुचारण पर आधारित ग्रामीण समाजों में जलवायु कठिनता एवं उच्चावचीय प्रतिकूलता वाले स्थानों पर पाये जाते है।

c) गांव (village) :- गांव में गृहों की संख्या 10 या 10से अधिक होती है। गांवों की प्राप्ति उच्च भूमि उर्वरता वाले प्रदेशों में देखी जाती है।

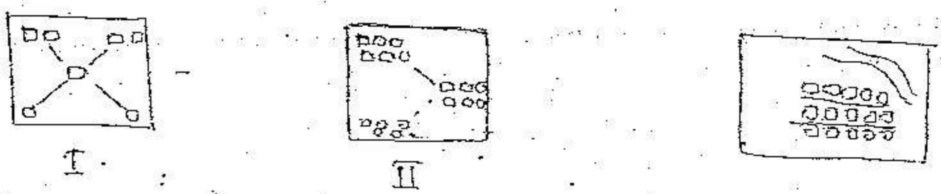

I. Farmsted — II Hamleted. — Village

ग्रामीण गृहों के प्रकार :- भारतीय जनसंख्या आयोग 2001 में ग्रामीण गृहों के प्रकारो को 3 आधार पर वर्गीकृत किया है।

a) कच्चे गृह : इनमें गृह की दोनो इकाइयाँ (दीवाल + छत) कच्चे पदार्थों अर्थात् मिट्टी, बांस, घास, ईंट एवं पत्थरों के छोटे टुकडों से निर्मित होती है। यह गृह आर्थिक पिछडेपन की निशानी है।

b) अर्द्ध कच्चे गृह :- ऐसे गृहो में कम से कम 1 इकाई (छत/दीवार) पक्की संरचना से निर्मित होती है जिसमें cement etc. पदार्थ का प्रयोग किया जाता है।

c) पक्के गृह :- जिनकी दोनों इकाइयाँ पक्के पदार्थ से निर्मित होती है।

Types of Rural settlement :- ग्रामीण बस्तियों के प्रकार से आशय गृहों के विशिष्ट समूहन से है जिसमें गृहों की संख्या, घनत्व, उनके मध्य की पारस्परिक दूरी etc. का विश्लेषण किया जाता है।

इन प्रकारों का वर्गीकरण हम नि. लि. 2 मात्रात्मक विधियों के आधार पर कर सकते है :

a) Coefficient of Disperse Method (विसरण गुणांक विधि):

$$C = \frac{n \times p}{P}$$

जहाँ

n = गृहों की संख्या

P = कुल जनसंख्या

p = उस अधिवासीय क्षेत्र से प्रतिस्थापित हो रही जनसंख्या या खण्डित अधिवास को प्रदर्शित करता है

इस विधि के आधार पर यदि C का मान शून्य हो तब सर्वाधिक समाकित सघनता वाला अधिवास प्राप्त होगा तथा इसके ~~यदि~~ बढ़ती मान के ~~साथ~~ क्रम में विरलता प्राप्त होती जायेगी

b) Nearest Neighbour Paradigm Approach (समीपस्थ पड़ोसी प्रतिमान)

$$R_n = 2d\sqrt{(N/A)}$$

यहाँ

d = दो गृहो या 2 गाँवों की मध्य की दूरी है

N = गृहों की संख्या / गाँवो की संख्या (क्षेत्र विशेष में)

A = कुल क्षेत्र

इस सूत्र के आधार पर यदि R_n का मान 1.25 से कम प्राप्त होता है। उसे सघन बस्ती कहेंगे। यदि R_n = 1.25 से 1.5 के मध्य हो तो उसे अर्ध सघन बस्ती कहेंगे।

$R_n \geq 1.5$ → विरल बस्ती

$R_n = 0$ → संपूर्ण अधिवास एक ही केन्द्र पर अवस्थित है।

इन उपागमों के आधार पर हम ग्रामीण अधिवास को निम्न 4 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं

1. सघन अधिवास (Compact)
2. अर्द्ध सघन अधिवास (Semi-compact)
3. पुर्वा युक्त — " — (Hamleted)
4. प्रकीर्णित अधिवास (Dispersed)

सघन अधिवास :- इसे Nucleated settlement, concentrated settlement etc के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिवास एकल केन्द्रीय होते हैं। जिसमें मकान / अधिवास पास-पास या सटी हुई होती है तथा इनके चारों ओर खेत खलिहान व बगीचे होते हैं। यह अधिवास मानव की सामाजिक संगतता, सुरक्षा, नैसर्गिक प्रवृत्ति etc स्वरूप के आधार पर निर्धारित होते हैं। इन अधिवासों के उद्भव एवं विकास में भू-भौतिक दशाओं की अनुकूलता, समुदाय की पारस्परिक निर्भरता, समुदाय का आर्थिक सामाजिक संगठन etc कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

ex — Japan, China, Indonesia के Java, Pakistan.

India में उर्वर मृदा क्षेत्र ex - गंगा यमुना दोआब, N. Haryana, भारत का delta क्षेत्र, Malwa Plateu, तटीय क्षेत्र।

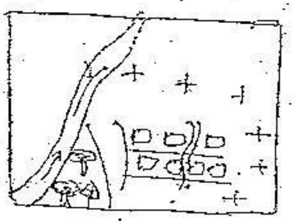

Semi-compact settlement :- अर्धसघन अधिवासों का विकास सामाजिक केन्द्रीयता एवं विकेन्द्रीयता का परिणाम है। यह विकास मध्यवर्ती सामंती व्यवस्था का परिणाम है जिसमें गांव के मूल केन्द्र में एक अधिवास क्षेत्र तथा ग्रामीण सीमा। गांव से कुछ दूरी पर अवस्थित 1 या 1 से अधिक पुर्वे होते हैं। इस अधिवास में प्रमुख केन्द्र को "खास/कला" एवं पुर्वों को 'खुर्द या नगला' बोला जाता है।

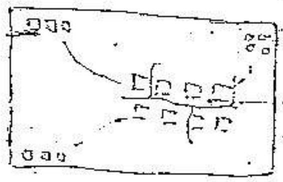

इस प्रकार के अधिवास विश्व स्तर पर S एवं SE Asia के मानसूनी में पाये जाते हैं।

भारत में, निचले गंगा के मैदान, गंगा यमुना दोआब के पश्चिमी भाग, मालवा पठार, Bundelkhand एवं बघेलखण्ड etc में पाये जाते हैं।

पुर्वा युक्त ग्रामीण अधिवास: अर्द्ध सघन अधिवास से इस अधिवास में अंतर इस बात को लेकर है कि संपूर्ण ग्राम में कोई मूल अधिवास केन्द्र नही होता बल्कि संपूर्ण बस्ती छोटे-2 पुर्वों में विभाजित होती है। परन्तु इन बस्तियों में बिखराव के बावजूद सामाजिक जीवन का मेल मिलाप एवं परस्पर सहयोग की भावना में कोई कमी नही देखी जाती।

वितरण :- गंगा - घाघरा दोआब, पार घाघरा मैदान, CNP, बिन्ध्य की उच्च भूमि क्षेत्र etc.

विश्व स्तर पर अरब देशों मे Egypt, Algeria, Libya, Yaman etc. इसके etc. है।

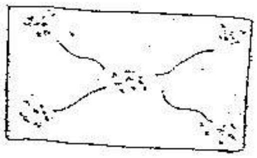

प्रकीर्णित / विरल अधिवास :- लघु आकार तथा एकाकीपन से युक्त जीवन में इन अधिवासे में सामान्यत: 1 झोपड़ी से लेकर 1 परिवार तक जिसमें पशुग्रह, आवासग्रह, गोदाम etc शामिल होती है। आदि इकाइयाँ प्रकीर्णित अधिवास के ex. है। ये मुख्यत: जनजातीय कृषि प्रदेशों मे मिलते है जहाँ भूमि की उर्वरता अत्यंत निम्न, भू संरचना जटिल, जलवायु अत्यंत कठिन पायी जाती है।

इन अधिवासों के अपने सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारण भी है ध्यातव्य है कि जहां पुराने विश्व में इस तरह के अधिवास विषम भू भौतिक दशाओं में पाये जाते है वही नई दुनिया के देशों में आर्थिक संवृद्धि ...

सुविधाओं के उपलब्धता के परिचायक है।

Ex - विश्व - USA, Canada, Argentina का Pampas Plain एवं Europe का आधुनिक समाज

भारत - राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, लेह, लद्दाख, NE का दुर्गम पहाडी क्षेत्र या अन्य भौगोलिक प्रतिकूलता वाले स्थानों मे

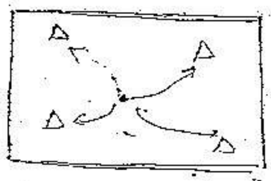

ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। प्रतिरूप से आशय एक ऐसी विशिष्ट संरचना से है जो कि ग्रह विन्यासों के समूहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है।
ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप को सघन, अर्द्ध सघन एवं विरल अधिवास प्रतिरूप के आधार पर कई अन्य उपप्रतिरूप मे विभाजित किया जाता है।

Ex - A) सघन अधिवास के अंतर्गत -

a) आयताकार प्रतिरूप
b) वर्गाकार प्रतिरूप
c) रेखिक प्रतिरूप
d) चक्रीय —
e) अरीय —
f) त्रिभुजाकार प्रतिरूप
g) तीर नुमा
h) L - shaped आदि प्रतिरूप

B) अर्द्ध सघन प्रतिरूप -

a) गिरि पाद पर
b) Horse shoe
c) Hill top

आयताकार प्रतिरूप :- उच्च उर्वरता युक्त गंगा के मैदान में जिनमे ग्रामीण अधिवास में गृहों का विन्यास, विभिन्न सडकों के दोनो तरफ एक क्रमिक व्यवस्था के रुप में पाया जाता है।

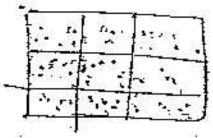

छिद्र युक्त आयताकार प्रतिरूप :- ऐसे प्रतिरूपो में केन्द्रीय भाग मे मंदिर, तालाब etc. पाये जाते है।

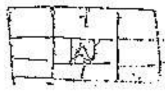

वर्गाकार प्रतिरूप :-

Ex. - पंजाब के मैदानी भाग, 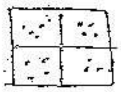
मिथिलांचल (NW Bihar), अवध etc क्षेत्रों में पाये जाते है। —

विश्व - Indonesia का Java, Sind क्षेत्र (Pak), Iceland के तटीय अधिवास

छिद्र युक्त वर्गाकार

वृत्ताकार :- बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा हेतु विभिन्न गृहे का विकास एक केन्द्र के चतुर्दिक हो जाता है जिससे पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग का भाव दृष्टिगोचर होता है।

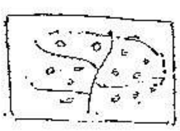

छिद्र युक्त चक्रीय अधिवास

रैखिक अधिवास : मुख्य नदी या परिवहन मार्गों के सहारे तटीय मैदान मे भी +nt

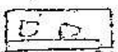

Ex. - मालाबार coast

Herring bone Pattern :- जब मुख्य परिवहन मार्ग से क्षेत्रीय सड़के लंबवत रूप से मिलती है तब ऐसा प्रारूप विकसित होता है।
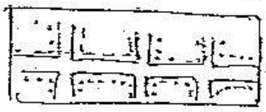
NOTE: सघन अधिवासों के अन्य Ex - Booklet से देखे।

अर्धसघन :- ऐसे अधिवासों में जमीन की उत्पादकता कम होने से सापेक्षिक घनत्व कम पाया जाता है। कृषि कार्य में पशुपालन की महत्ता भी बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत निम्न प्रारूप विकसित होते है

a) Horse shoe Pattern :- गिरिपाद पर अवस्थित प्रतिरूप इसका प्रमुख उदा. है।

Ex - हरिद्वार, विन्ध्य की विलगित पहाड़ी क्षेत्रों का दक्षिण भाग

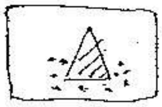

विश्व - USA का Great plain, Andies के पूर्वी ढालों पर भी इस प्रकार का अधिवास +nt

b) Hill top-Pattern :- इस प्रकार का प्रतिरूप का सर्वोत्तम - Nagaland में नागा जनजाति का अधिवास क्षेत्र है। ये जनजातियां सुरक्षा के दृष्टिकोण अपना अधिवास पहाड़ी शीर्ष पर अधिवासित करती है।

विश्व - Tajakistan, Kirgistan, Uzbekistan (Central Asia)

शेष Printed notes से।

Dispersed settlement Pattern :- इसमें गृहों के एकाकी विन्यास के कारण सामान्य प्रतिरूप विकसित नही हो पाता जिससे विलम्बित पूर्वा युक्त अधिवास / एकाकी अधिवास विकसित होते है।

Ex- पश्चिमी राजस्थान, लेह, लद्दाख

Rural Morphology :-

RM से तात्पर्य गांव की आंतरिक संरचना से है जिसके अंतर्गत समाज की भौतिक सामाजिक एवं प्रकार्यात्मक विन्यास का विवेचन किया जाता है।

भारतीय RM को निम्न तीन वर्गों में रखा जाता है।

(1) भौतिक आकारिकी :- इसके अंतर्गत सडक मार्गो की संरचना जिसमें Road to Road, Road to अधिवास का संबंध etc तथा गृहों का विन्यास जिसमें प्रत्येक गृहों का आपसी अंर्तसंबंध, गृह का सडक, नदी etc से अंर्तसंबंध, गृह का कृषि भूमि, चारागाह, खलिहान etc का अंर्तसंबंध देखा जाता है। इसके अंतर्गत नदी, नाले, तालाब etc का भी वर्णन सम्मिलित होता है।

(2) सामाजिक / सांस्कृतिक आकारिकी :- इसके अंतर्गत जातीय समूहन, धार्मिक एवं नृजातीय वर्गीकरण एवं आर्थिक आकारों पर किये गये ग्रामीण स्वरूपों का विभाजन शामिल किया जाता है।

Case study - Model :- गांव के केन्द्र में ग्राम प्रधान / जमींदार का आवास होता है जिसके चारो तरफ स्वजातीय एवं पुरोहित वर्ग का अधिवास होता है।

द्वितीय वलय में मध्यम वर्ग का अधिवास होता है जो कि इस उच्च वर्ग को अपनी सेवा प्रदान करते है।
Ex- लोहार, सोनार, बागवान etc.

तृतीय वलय सामान्यतः धुर्वा युक्त होता है जिसमें कामगार कृषकों एवं अछूत वर्गों का अधिवास प्राप्त होता है। इसे हम Doxadis model द्वारा निम्न रुप में प्रदर्शित कर सकते है,

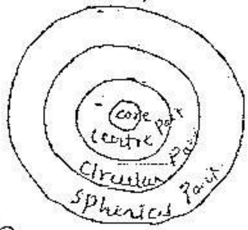

a) core zone :- मुखिया / जमींदार वर्ग

b) Centre part :- मध्य वर्ग का अधिवासीय क्षेत्र

c) Circular Part :- इस पर विकेन्द्रीकरण के परिणाम स्वरुप मिश्रित जातियाँ पायी जाती है।

d) Spherical Part :- यह मुख्य ग्रामीण अधिवास से थोड़ा दूर निम्न जातियों का अधिवासीय क्षेत्र होता है।

Functional Morphology

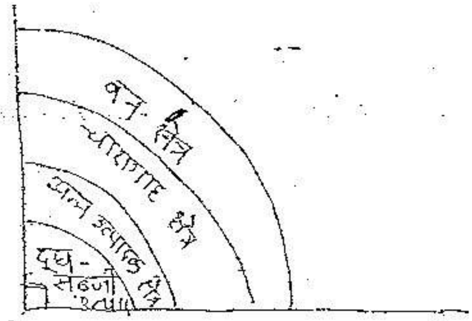

केन्द्र
(अधिवास)

पर्यावरणीय समस्या :-

भौतिक पर्यावरणीय समस्या :- ① वायु ~~प्रदेश~~ प्रदूषण जो ईंधन के जलने, गोबर गैस, दलदल क्षेत्र ।

② जल प्रदूषण

③ मृदा प्रदूषण

a) जहरीले रसायन एवं उर्वरक का प्रयोग

b) निर्वनीकरण से अपरदन में वृद्धि

c) भूमि के अतिउपयोग से

④ निर्वनीकरण

⑤ अतिपशुचारण

सामाजिक समस्या :- ① जातीय भेदभाव

② स्त्रियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण।

③ बुजुर्गों की स्थिति

④ सांप्रदायिक हिंसा

⑤ संयुक्त परिवार का टूटना।

⑥ ग्रामीण अपराध

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आध[illegible] आवश्यकता
ओं की अभावता

19/09/2012

क्षेत्रीय नियोजन

↓

उद्देश्य

Planning → Econo. Plan / Region Plan } मानव → आर्थिक / सामाजिक / सांस्कृतिक

↓

कब → क्यों → कैसे → पृष्ठ भूमि / उद्देश्य / परिणाम } → Multi Level Planning

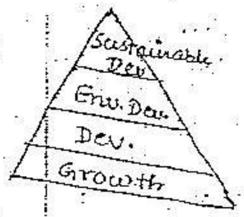

सतत विकास के वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राकृतिक कारक, प्रौद्योगिकी विकास एवं विभिन्न संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इन संस्थाओं के द्वारा अपनायी गई विकास प्रक्रिया नियोजन (Planning) है।

नियोजन :- नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पहचान करना तथा ऐसी नीतियों का निर्माण करना है जिससे इन उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

भारत में क्षेत्रीय नियोजन :- Alden एवं morgan के अनुसार R.P. न तो आर्थिक नियोजन है और न ही भौतिक आयोजन बल्कि यह मानवीय विकास हेतु जीवन के समस्त पक्ष ex. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राजनैतिक एवं भौतिक etc तत्वों का संश्लेषित रूप है। "यह एक ऐसी संकल्पना है जो प्रदेश की प्रत्येक समस्या को समाहित करती है।"

स्पष्ट है कि प्रादेशिक आयोजन का संबंध space (स्थान) एवं समाज दोनो से है।

इस संकल्पना में बहुस्तरीय नियोजन का महत्त्वपूर्ण स्थान है।
भारत में नियोजन प्रक्रिया का विकास एवं नियोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति विभिन्न FYP के माध्यम से की जा रही है।

पंचवर्षीय योजनाओं का विकास :-

पृष्ठभूमि :-
उद्देश्य →
कार्यनीति → आर्थिक / सामाजिक
सफलता / असफलता

संसाधन → आर्थिक / भौतिक } मानवीय
↓
दोहन
↳ लाभ
समान वितरण
आर्थिक नियोजन — कल्याण

1st FYP

पृष्ठभूमि - भारत आजाद हुआ
उद्देश्य - ① खाद्यान्न संकट
② पाकिस्तानी शरणार्थी पुर्नवास
③ तीव्र मुद्रास्फीति

सफलता - ✓ ✓

बहुस्तरीय नियोजन :- • नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति करना तथा ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

आरंभिक दौर में राष्ट्रीय नियोजन केवल केन्द्र एवं राज्य स्तर पर किये जाते थे परन्तु जनजागरूकता के अभाव एवं जनसहभागिता के अभाव के कारण योजनाओं से वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

परिणामतः 1977-78 में दांतेवाला समिति का गठन किया गया साथ ही अशोक मेहता समिति जिसमें से दांतेवाला समिति ने विकास ...

इस संकल्पना में बहुस्तरीय नियोजन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में नियोजन प्रक्रिया का विकास एवं नियोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति विभिन्न FYP के माध्यम से की जा रही है।

पंचवर्षीय योजनाओं का विकास :-

पृष्ठभूमि :-
उद्देश्य →
कार्यनीति → आर्थिक / सामाजिक
सफलता / असफलता

संसाधन — आर्थिक / भौतिक } मानवीय
↓
दोहन
↳ लाभ
समान वितरण
आर्थिक नियोजन — कल्याण

Ist FYP

पृष्ठभूमि - भारत आज़ाद हुआ
उद्देश्य - ① खाद्यान्न संकट
② पाकिस्तानी शरणार्थी पुनर्वास
③ तीव्र मुद्रास्फीति

सफलता -

बहुस्तरीय नियोजन :- • नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति करना तथा ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

आरंभिक दौर में राष्ट्रीय नियोजन केवल केन्द्र एवं राज्य स्तर पर किये जाते थे परन्तु जनजागरूकता के अभाव एवं जनसहभागिकता के अभाव के कारण योजनाओं से वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

परिणामतः 1977-78 में दांतेवाला समिति का गठन किया गया साथ ही अशोक मेहता समिति जिसमें से दांतेवाला समिति ने विकास ...

40-50 Day

NB पंचायती राज

नियोजन का अधिकार प्रदान किया गया। यह दोनों ग्रामवासियों के कल्याण हेतु आयोजनायें तैयार करते है।

पंचायती राज्य एवं विकेन्द्रीकृत आयोजन

→ पंचायत का विकास
– उद्देश्य
– सफलतायें
– चुनौतियाँ

पंचायत शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के "पंचायतन" से हुई है। इसका आशय 5 लोगों के समूह से था।

पंचायती राज शब्द से आशय स्थानीय ग्रामीण स्वशासन से है जो भारत के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा अधिकारों के विकेन्द्रीकरण एवं प्रजातंत्र की प्रक्रिया को आम लोगों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण साधन है।

पंचायतों का उद्देश्य ग्रामीणों मे आत्मविश्वास को जगाना तथा उन्हें आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना आयोजन एवं विकास के प्रति जागरूकता एवं प्रेरणा को उत्प्रेरित करना था। इस पद्धति के माध्यम से ग्रामीण अपने संबंध में या स्वहित के लिए निर्णय ले सकते थे।

भारत में पंचायतों का विकास प्राचीन काल से सभा एवं समिति के रूप में देखने को मिलता है। ब्रिटिश काल में भी पंचायतें ग्रामीण जनो के निर्णय की इकाई के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इस औपनिवेशिक काल में भी पंचायतें स्थानीय शासन की महत्त्वपूर्ण इकाई थी।

महात्मा गांधी ने भी अपने ग्राम स्वराज नामक पुस्तक में पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया है। फलतः राज्य के DPSP के अनु. 40 में इसे शामिल किया गया।

पुनः यह स्मरण रहे कि पंचायती राज व्यवस्था के गठन का मुख्य उद्देश्य " लोकतंत्र एवं प्रशासन को ग्रामीण स्तर पर ले जाना तथा आयोजन एवं विकास का विकेन्द्रीकरण करना था।

ग्रामीण लोगो मे आर्थिक आयोजन एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रति जागरुकता एवं उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। परन्तु यह सरकारी योजना ग्रामीणजनों में उत्साह भरने एवं उत्सुकता उत्पन्न करने में असफल रही। तत्पश्चात Block development committee का गठन किया गया लेकिन यह भी ग्रामीण जन का सहयोग प्राप्त करने में असफल रही।

इन दोनों समितियों द्वारा किये गये कार्यों की जांच करने एवं बेहतर क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा B.R. Mehta की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में NDC को सौंपी। फलतः लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश NDC द्वारा स्वीकार कर ली गई।

त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति लागू किया जाना इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश थी।

इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित था कि इन तीनों संस्थाओं को उचित अधिकार उत्तरदायित्व की प्राप्ति पूर्णता से होनी चाहिए जिसे निभाने हेतु संसाधनों की समुचित आपूर्ति की जाये तथा ये भी सिफारिश की गई कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रम इन संस्थाओं के माध्यम से ही क्रियान्वित किये जाये।

पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 Oct 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन PM Pt. J.L. Nehru द्वारा की गई। तत्पश्चात Andhra Pradesh एवं भारत के अधिकांश राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाया। लेकिन इन संस्थाओं में

(1) विभिन्न स्तरों की संख्या।

(2) जिला परिषद, ग्रामीण समिति एवं ग्राम पंचायत में क्या संबंध हो।

(3) इनके कार्य एवं कार्यकाल क्या हो; इसे लेकर विभिन्न राज्यों में आपसी अंतर था।

Ex- TN में द्विस्तरीय PRS जबकि TN में 4 स्तरीय PRS को अपनाया।

1977-78 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया जिसने पंचायतों के पुनर्उत्थान एवं मजबूती प्रदान हेतु द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की

(i) जिला स्तर पर जिला परिषद
(ii) मण्डल परिषद (15,000 - 20,000 जनसंख्या वाले क्षेत्र)
(iii) इसमें राजनैतिक पार्टी की भागीदारी होगी।
(iv) आर्थिक स्रोत हेतु कराधान की व्यवस्था।
(v) इनमें समुचित रूप से SC/ST आरक्षण की बात की गई।

लेकिन जनता पार्टी सरकार कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही भंग हो गई फलतः इनकी सिफारिशें लागू नहीं हो सकी।

पुनः 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु V.K. Rao की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसके अनुसार विकास, प्रशासन लोकतंत्रीकरण के विपरीत नौकरशाही के चंगुल में फसकर रह गया है। फलतः PRI कमजोर एवं पतनोन्मुख हो गई है। जिसे V.K. Rao ने 'बिना जड की घास' की संज्ञा दी।

तदुपरांत Rajiv Gandhi govt. ने उत्थान एवं पंचायत राज संस्थान के उत्थान हेतु L.M. Singhvi की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

उल्लेखनीय है कि PRI की अनेक उपलब्धियों के बावजूद भी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी जिसके आलोक में नि. लि. कारणों को देखा जा सकता है।

(1) इनके संरचनात्मक स्तरों को लेकर अस्पष्टता → द्विस्तरीय / त्रिस्तरीय / चतुर्थ स्तरीय

(2) संकल्पनागत जटिल - अर्थात ये संस्थायें नीतियों के क्रियान्वन की इकाई हो या निर्माण या प्रबंधन की ?

(3) राजनैतिक उदासीनता

(4) नौकरशाही की महत्त्वपूर्ण नकारात्मक भूमिका

उपरोक्त समितियों के सुझाव लागू करने एवं पंचायतों के असफलता को दूर करने हेतु 1991-92 मे '73 वे संविधान संशोधन' द्वारा पंचायती राज्य संस्थानो का संवैधानीकरण कर दिया गया परिणामतः इन संस्थाओं को ग्रामीण उत्थान के लिए योजना बनाना तथा इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना आदि का दायित्व प्रदान कर दिया गया तथा राज्य सरकार को यह अनुदेश दिया गया कि इन संस्थाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाये वर्तमान में Delhi को छोड़कर सभी राज्यों तथा UT में एक सुदृढ़, व्यावहारिक जिम्मेदार पंचायतों का गठन किया गया। जिसके लिए वित्तीयन निम्न 3 तरीको से किया जाता है :-

(1) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों से प्राप्त अनुदान

(2) राज्य स्तरीय वित्त आयोगो की सिफारिशों से प्राप्त अनुदान

(3) केन्द्र व राज्य स्तरीय योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त धनराशि

(4) स्थानीय संसाधनों पर कर का आरोपण

PRI के समक्ष चुनौतियाँ :-

04/09/2012

Von Thunen Model

Introduction :- Von-thunen का कृषि अवस्थिति सिद्धान्त भूगोल में तंत्र विश्लेषण एवं स्थानिक परीक्षण का प्रथम उदाहरण है जो 'Isolated stage' नामक पुस्तक में 1826 में प्रकाशित हुआ। (विलगित प्रदेश)

भौगोलिक विषयों में मात्रात्मक प्रयोग एवं कृषि निर्माण का प्रथम उद्भूति है जो नव शास्त्रीय अर्थ विज्ञान से प्रेरित है। यह कृषि में शस्य प्रतिरूप एवं शस्य संयोजन तथा फसल चयन के आधार पर अधिकतम लाभ प्राप्ति को दर्शाता है।

Von-Thunen का उद्देश्य बाजार से बढ़ती दूरी के साथ घटती शस्य गहनता एवं बढ़ते परिवहन मूल्य के आधार पर फसल प्रतिरूप की स्थापना करना है जिसमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

(margin: भावात्मक / निगमनात्मक / अनुभव के आधार पर घर में बैठ कर कल्पना और मौलिक वस्तु में ...)

यह एक आदर्शवादी निगमनात्मक मॉडल है जो सामान्यीकृत अवधारणाओं पर आवलंबित है।

अवधारणायें :

① Isotropic surface :- एक समान भूदृश्य जहाँ जलवायु, स्थलाकृति भूभौतिक समरूपता है।

② प्रत्येक ~~मानव~~ मानव आर्थिक एवं विवेकशील मानव है।

③ दिया गया भूदृश्य किसी भी बाह्य प्रभाव से अप्रभावित तथा एक ही राजनैतिक तंत्र से प्रशासित है।

④ भूमि की उर्वरता भूदृश्य पर एक समान है।

⑤ बाजार के केन्द्र में होने के कारण सभी दूरियाँ अरीय (Radial) दूरी है।

⑥ एक ही नृजातीय अथवा संस्कृति की जनसंख्या रहती है।

आर्थिक संकल्पनायें :-

① बाजार में मांग एवं मूल्य दोनो नियत है। (कृषि अवस्थापना)

② परिवहन लागत वस्तु के भार एवं दूरी का गुणनफल होता है।

T.C. = kg × d

③ TC वस्तु के भार, दूरी एवं विनष्टता तथा Bulk, volume का समानुपाती होता है

TC = d × w

P. Perishability विनष्टता

T.C ∝ P · bulk distance · weight

④ - परिवहन का एक ही साधन है तथा परिवहन लागत भी नियत है।

कृषि अवस्थिति सिद्धान्त ये Locational Rent ** (अवस्थिति लगान) पर आधारित है जो आर्थिक लगान के रूप में भी एक जाना जाता है।

Locational Rent :- 1818 में Recardo ने सर्वप्रथम आर्थिक लगान की संकल्पना दी है हालांकि Von thunen का विचार Recardo से स्वतंत्र है। Recardo ने बाजार से दूरी के साथ मृदा की उर्वरता को घटते क्रम में माना है। बाजार O के पास जोत भूमि A पर कृषि होती है परन्तु जनसंख्या बढ़ने पर B एवं C पर भी कृषि कार्य होंगे।

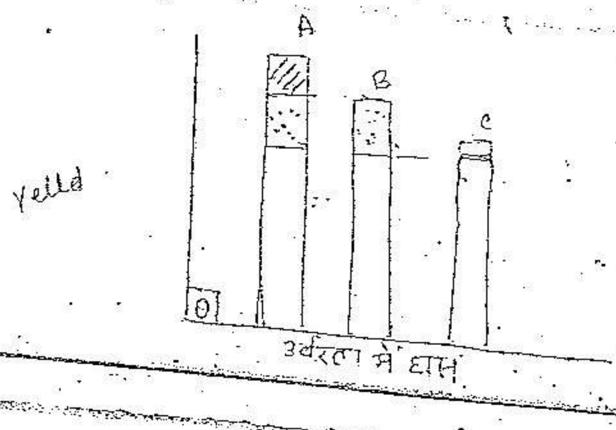

7) वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि (commercialised grain farming) :-

उच्च मशीनीकरण, वाणिज्यीकरण,
मुख्य विस्तार - स्टेपी, प्रेयरी जैसे क्षेत्रो में
विस्तृत कृषि प्रणाली
एकफसलीय चक्र होते है तथा कृषक को suitcase farmer कहा जाता है क्योंकि किसान नगरों में रहते है तथा Harvesting के Time पर वापस आ जाते है।

8) Commercial dairy farming :-

Denmark, NZ का Taranaki मैदान (दुनिया में सर्वाधिक गाय का घनत्व प्राप्त होता है।,

→ food processing Ind.
→ मक्खन, पनीर

9) Commercial grain & Livestoke :-

Ex Volga घाटी, E Europe, बाल्टिक घाटी,
New England (US)

10) Subsistance grain & Livestoke :-

Ex - M.P. Gangatic Plain
Western Plain of china.
Coastal brazil, Paragua, Colombia, Bolivia

11) Meditterean Agriculture :-

a) Oriental :- निर्वहनीय → भूमध्य सागर के चारों तरफ

b) Oxidental :- व्यापारिक, मध्य चिली, cape town,
Australia का दक्षिणी Tip,
California

12) <u>Plantation</u> :- Malaysia, Indonesia, Srilanka.
India - पूर्वी तट, केरल तट, असम,
→ उपनिवेशवाद का परिणाम है।
→ गैर पारिस्थितिक कृषि है।
→ वाणिज्यिक
→ Labour intensive
→ Industrial crop होते हैं।

13) <u>Horticulture (उद्यान कृषि)</u> :- Market gardening इसके अंतर्गत सब्जी उत्पादन, फल, फूल उत्पादन, dairy farming इसे ~~भारत में~~ Track farming भी कहते हैं।

<u>Anderson</u> : इन्होंने 4 प्रमुख वर्ग बनाये -

a) Ecological & Near Ecological - 1 + 2

b) commercial - 3 + 7 + 8 + 9 + 11b + 12 + 13

c) Subsistance -

d) collective farming → co-operative,
→ State farming (sov. khoz रूस में)

इस प्रकार Anderson ने 16 वर्ग दिये

13 + co-operative + State farming + occidental

उत्तरदायित्व किसी पर नहीं

आर्थिक लगान वह अतिरिक्त लाभ है जो भूमि A, B पर प्रदान करती है। क्योंकि A की उत्पादकता B से अधिक है।

Von thunen ने अवस्थिति लगान में बाजार से दूरी के साथ उर्वरता को एक समान माना परन्तु TC में वृद्धि के आधार पर अवस्थिति लगान की कल्पना करते हैं। भूमि A पर यदि फसल आलू का उत्पादन किया जाये तथा B, C पर भी उसी फसल को उपजाए तो कुल उत्पादन एक समान परन्तु परिवहन लागत में अंतर के कारण लाभ प्राप्ति प्रत्येक भूमि से अलग-2 होंगे।

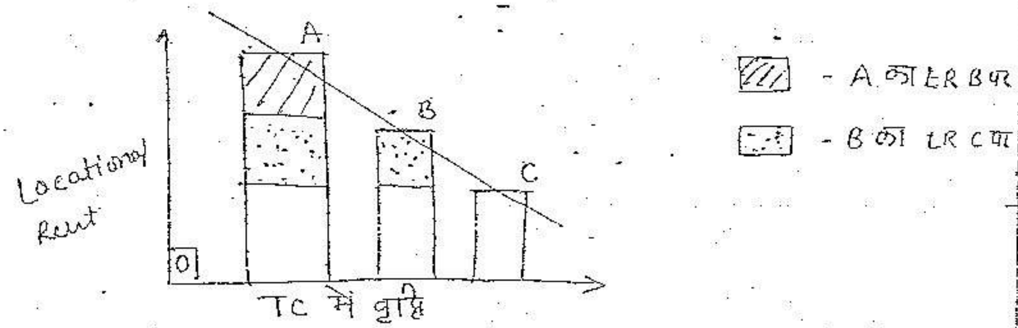

अवस्थिति लगान वह अतिरिक्त लाभ है जो भूमि A, B के ऊपर परिवहन लागत में बचत के कारण प्राप्त होता है।

Shop No.- A-35/36,
Dr. Mukherjee Nagar Delhi
Phone : 011-27

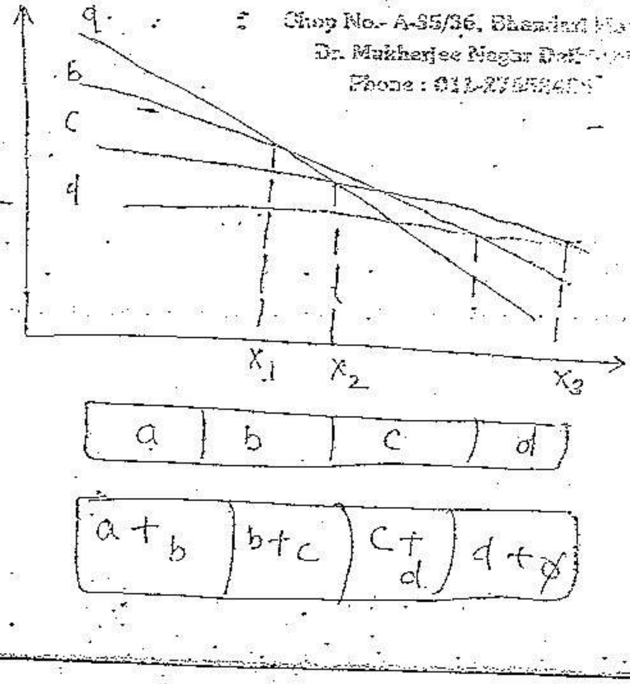

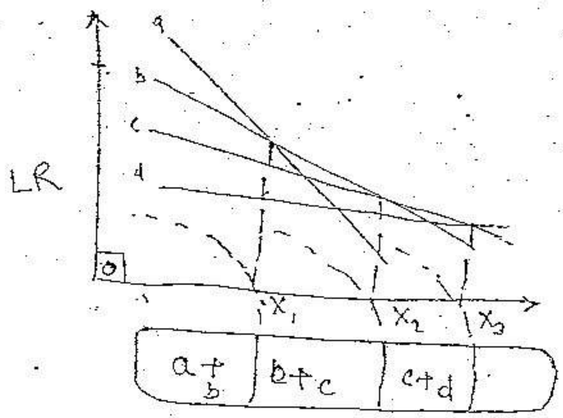

Von thunen ने 7 फसलो के अवस्थिति स्थान की गणना की तथा एक ही ग्राफ पर अध्यारोपित कर दिया।
तथा वलयाकृतिक प्रदेशों की प्राप्ति तथा शस्य संयोजन एवं शस्य गहनता के आधार पर 2 model निर्मित किये -

भूमि प्रयोग गहनता मॉडल (शस्य गहनता मॉडल) :- बाजार से दूरी के साथ शस्य गहनता घटती है क्योंकि परिवहन लागत में वृद्धि होता है अत: समीपवर्ती दूरी पर अधिक उत्पादकता परिवहन लागत पर बचत कर सकती है।

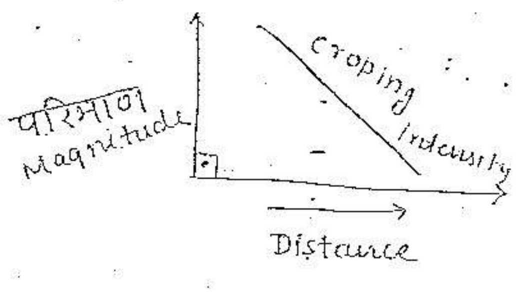

शस्य संयोजन मॉडल :- केन्द्र में बाजार यह 0.1% भूमि अधिगृहित करता है तथा भूदृश्य से अरीय दूरी के कारण सुगम्य है यहां मांग एक मूल्य नियत है।

वलय-I - बाजार कृषि 1% भूद्दश्य पर, फल, सब्जी, दुग्ध उत्पादन क्योंकि इनके भार, Bulk, विनश्वरता अधिक होते हैं।

वलय-II - वानिकी - 3% भाग पर, 19वीं शताब्दी में ईंधन के साधन के रूप में लकड़ियों का प्रयोग होता था तथा इन पर परिवहन लागत अधिक होता है अतः बाजार के समीपस्थ माना गया।

वलय III :- गहन खाद्यान्न कृषि जिसमें 6 वर्षीय शस्य फसल चक्र प्राप्त होते है। यह भूमि का 3% तथा शस्य चक्र Rye - Rye - Oat - Potato - Vetseeh = Fodder

वलय IV :- Extensive grain farming - 7 वर्षीय फसल चक्र प्राप्त होते है।

- यह 1/3rd or 33% भाग पर है तथा इसमें I वर्ष पर्ती भूमि रखी जाती है।

Rye Rye - Oat - Fodder - Vetseh - Fodder - Fallow

वलय V :- Three field system - 25% भूद्दश्य को अधिग्रहित करता है।

तथा 1/3rd भूमि खाद्यान्न, 1/3rd Fodder तथा 1/3rd पर्ती भूमि रखी जाती है।

वलय VI :- विस्तृत चारागाह कृषि - 34.9% पर फैला है यह मवेशी पालन, ~~पशुपालन~~ पशुचारण

Sheep razing मांस, चमड़ा, ऊन के लिए

इसके चारो ओर uncultivated wilderness व्याप्त है जो भविष्य में कृषि में प्रयुक्त होगा।

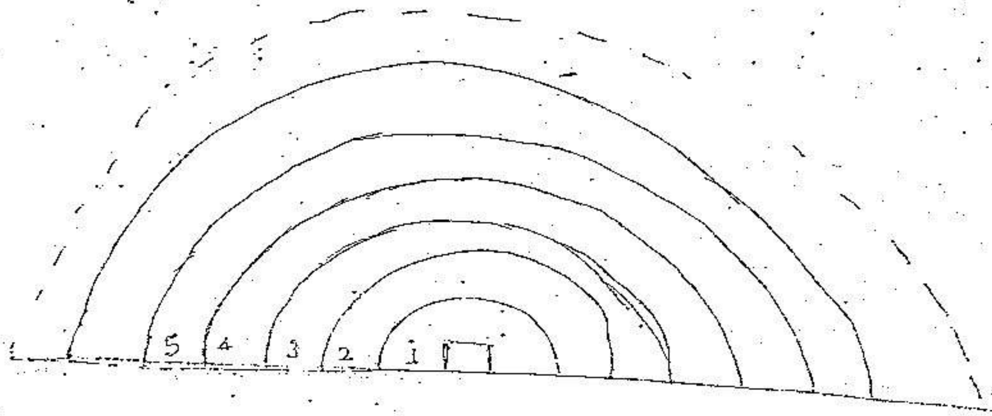

- Von thunen ने 2 modification बतलाये जिसमें वलयाकृतिक प्रदेश विरूपित होकर Elongated आकृति को ग्रहण कर सकता है :

<u>Modification - I</u> :- यदि बाजार को कोई नदी जोडती चूँकि नदी मार्ग में परिवहन लागत कम होता है एवं नौगम्यता भूपरिवहन (घोडा गाडी) से ~~अल्प~~ तीव्र होगी अतः बाजार कृषि एवं woodlands नदी के किनारें समानान्तर विकसित हो जाते है।

<u>Modification II</u> :- यदि भूदृश्य पर एक अन्य बाजार विकसित हो जाये तो वह अपना बाजार कृषि व वानिकी क्षेत्र विकसित करता है जिससे अन्य वलयाकृतिक प्रदेशों पर भी प्रभाव पडता है।

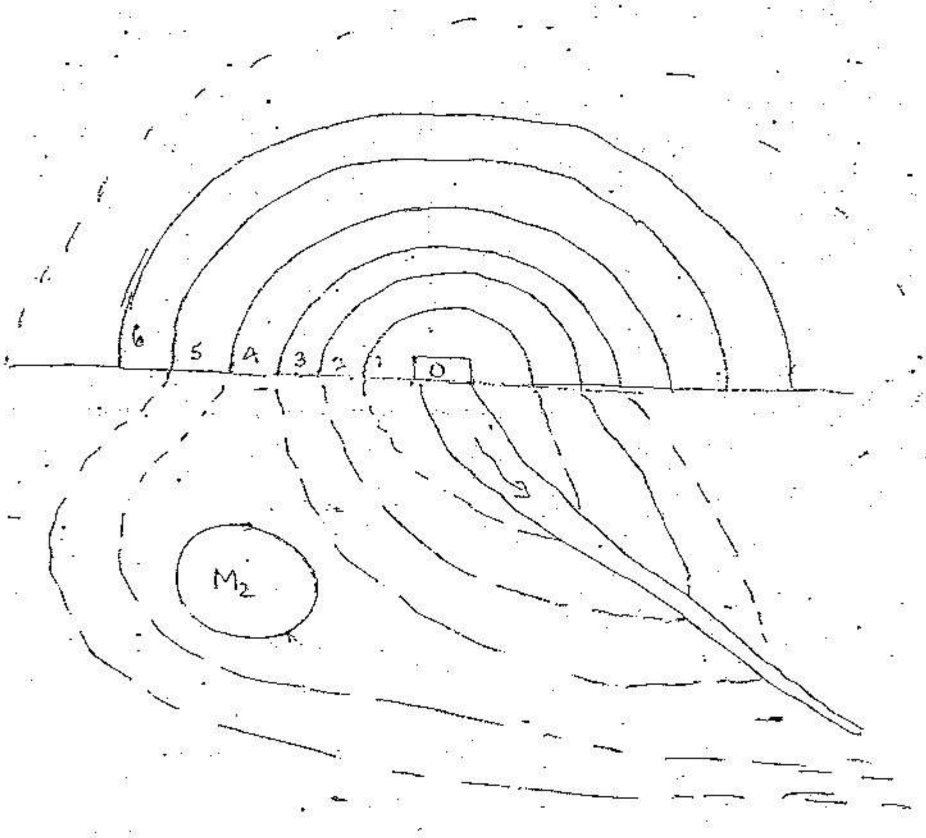

THE BOOK SHOP
Shop No.- A-35/36, Bhandari House
Dr. Mukherjee Nagar Delhi-09
Phone : 011-27658485

Application/मूल्यांकन :- यह model आदर्शवादी निगमनात्मक होने के कारण भू दृश्य के वास्तविक से परे है परन्तु इसके आधारभूत सिद्धान्त Ex - फाटक की विवेचना, शस्य गहनता का आंकलन सिद्ध है। आदर्शवादी model का उद्देश्य भूदृश्य के पूर्ण सत्य को दर्शाना नही होता बल्कि कुछ प्रायोगिक चरो के प्रभाव को स्थापित करना होता है। ये Model Parameter अथवा Yard stick की तरह कार्य करते है जिससे भू दृश्य की विरूपता एवं कारणों को समझा जा सकता है।

इस model को अप्रासंगिक / outdated model माना गया क्योंकि -

① परिवहन में क्रांति

② ऊर्जा संसाधन में क्रांति

③ कृषि में क्रांति के कारण शस्य संयोजन प्रणालियाँ एवं शस्य गहनता तथा वानिकी का नगरों के समीपस्थ होना असिद्ध होने लगे।

④ प्रशीतलन की सुविधा के कारण विनष्टता का प्रश्न घटा।

Von Thunen में अन्य कई दोष है

Ex - ① एक ही बाजार को मानना

② मांग एवं मूल्य को नियत करना etc.

यह एक सीमित मॉडल है क्योंकि वाणिज्यिक कृषि प्रणालियों पर लागू हो सकती है निर्वहन कृषि प्रणाली पर नही क्योंकि कृषि का उद्देश्य सदैव लाभ प्राप्ति नही होता।

⑤ European फसलों पर आधारित है अत: उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में प्रासंगिकता घटती है

इस model को 3 पैमाने पर विभाजित दर्शाया गया है (Chisolm द्वारा - Father of Economic Geo)

a) <u>Continental Scale</u> - Ex - Europe पर

Europe में बाजार क्षेत्र BeniLux देश अथवा London - Paris △ को माना गया है। यहां बाजार कृषि प्राप्त होती है तथा Europe में अधिकतम गहन कृषि ~~...~~ प्रणालियां है।

→ Ring II ⇒ absent

→ Ring III ⇒ UK के midland तथा France, Italy, Germany तथा ~~पूर्वी~~ मध्य यूरोपीय

देशों में प्राप्त होता है।

Ring IV - पूर्वी यूरोपीय देश Ex- Ukrain, Romania, Bulgaria, Czech, Baltic देशों में प्राप्त

Ring V - Volga basin तथा मास्को के आसपास क्षेत्र एवं caspean तट पर दिखता है।

Ring VI - Scotland, Scandinevia, Ural region, Alps region की तरफ फैले हुए हैं।

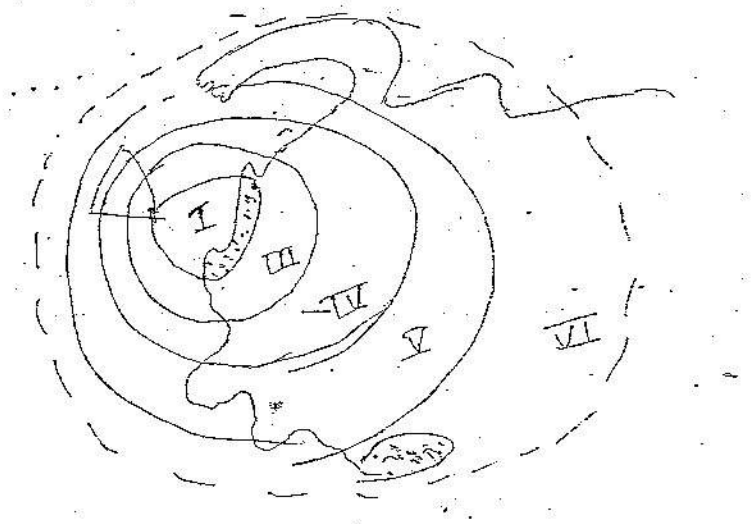

National Scale - US के New England क्षेत्र में Ring I जबकि Ring II Lake region में।

Ring III - मध्य एवं पूर्व US जहां खाद्यान्न कृषि है।

Ring IV - प्रेयरी का मैदान जहां विस्तृत खाद्यान्न कृषि है।

Ring V - wet plains of US जहां मिश्रित कृषि प्रणालियां हैं।

Ring VI - Rockies के ढलान।

भारत में Von thunen model लागू नहीं होता क्योंकि भूदृश्य विषम है जनसंख्या सघन एवं वितरि-त तथा निर्वहन कृषि प्रणालियाँ है। हरित क्रांति के क्षेत्र में यह model आंशिक सत्य के रूप में दिखता है।

Ex- Delhi को बाजार मानकर NCR बाजार कृषि का क्षेत्र है। Ring II ⇒ absent

Ring III ⇒ हरित क्रांति के प्रदेश

Ring IV ⇒ मे शस्य-गहनता कम है जो Raj, MP, UP, Uttarakhand तथा Shivalik की ओर प्राप्त होता है।

Ring V - अरावली प्रदेश की ओर एवं इन घाटियों में भी इसका परिदृश्य मिलता है।

Ring VI - पश्चिमी Raj एवं Trans himalaya क्षेत्र में फैले हुए है।

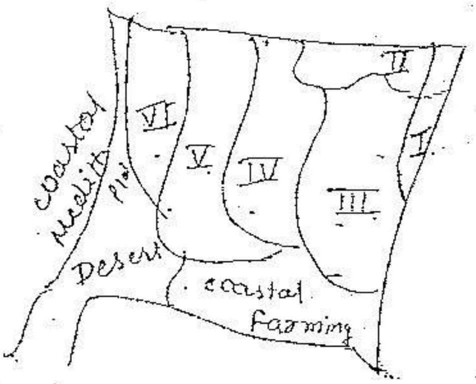

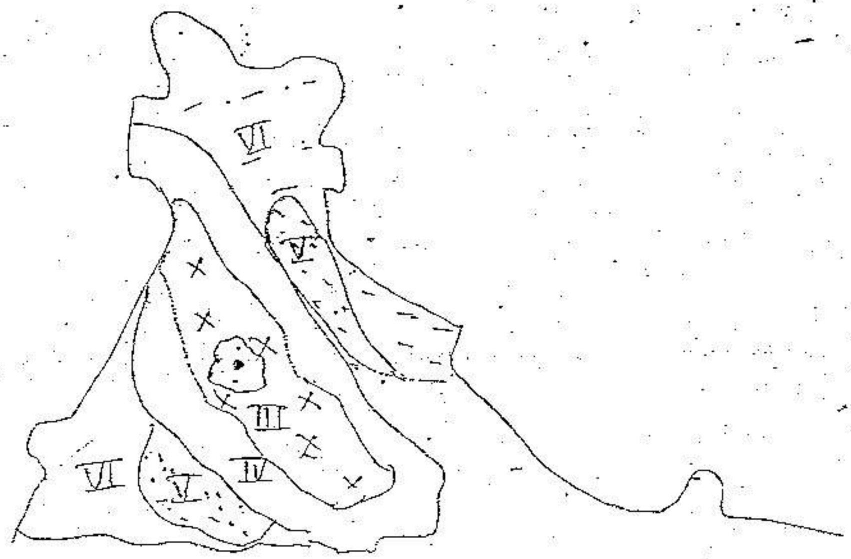

THE BOOK SHOP
Shop No.-A-35/36, Bhandari House
Dr. Mukherjee Nagar Delhi-09
Phone : 011-2765...

05/09/2012

Eco. geo. -I { Famine - Causes & effect
Trade Pattern - (WTO & Trade)

Agri Geog.

Eco -I — Agri II, Resource II, Industry II

Introduction :- कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रिया है जो मृदा पर आधारित है। यह एक पूर्णतः भौतिक आर्थिक क्रिया न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं मानव के पर्यावरणीय अनुकूलता तथा उसके ~~आर्थिक~~ कामनाओं (Economic aspiration) की अभिव्यक्ति होता है। कृषि प्रतिरूप सिर्फ भौतिक कारकों से प्रभावित नहीं होता बल्कि सामाजिक एवं संस्थागत कारक के प्रभाव परिलक्षित होते हैं।

Croping Pattern

Green Revolution & its impact :- हरित क्रांति का अर्थ है Genetically modified बीजों अथवा Transgenic बीजों जिन्हे HYV (High yeilding variety) कहा गया के आधार पर तीसरी दुनिया के देशों के अन्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि जिसने सैकडों वर्षों के खाद्यान्न संकट को दूर किया।

इस शब्द की रचना Prof. Gatt ने 1967 में की जो तीसरी दुनिया के कृषि उत्पादकता पर एक विचार है।

हरित क्रांति का प्रारंभ Mexico में Norman Borlaug ने किया जो गेहूँ के 2 variety

Norin-10 (Japan) एवं Mexican α के ~~hybridisatio~~ hybridisation से किया गया। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ M.S. Swaminathan के निर्देश में 1961 के Pilot Project IADP के रूप में प्रारंभ किया गया।
(राजस्थान - पाली, जालंधर, अलीगढ़, शाहाबाद, रायपुर, गोदावरी, तंजाबुर)

Intensive Agriculture development Proj

1964-65 Third plan में IAAP (Intensive Agriculture Area dev. Programme) प्रारंभ किया गया जिसमें 32 जिले सम्मिलित किये गये। परन्तु हरित क्रांति का प्रारंभ HYV prog.-1967 से माना जाता है। जिसे package prog. की संज्ञा दी गई।

→ बौना पौधा
→ canopy बड़ा बनता है।
→ कम समय में पक जाता है।
→ दाना बड़ा होता है।

हरित क्रांति के आधार :-

1. High yielding variety Seed
2. Irrigation (सिंचाई)
3. रासायनिक उर्वरक व NPK की उचित मात्रा
4. कीटनाशक, खरपतवार नाशक का उपयोग
5. Command area development proggramme → 1974-75
   ↳ Green Rev. को boost करने के लिए।
6. ग्रामीण विद्युतीकरण - सबसे पहले Haryana का विद्युतीकरण उसके बाद Punjab
7. मशीनीकरण
8. Agricultural Marketing. (कृषि विपणन)
9. ग्रामीण साख (credit)
10. ग्रामीण अवसंरचना Ex. सड़क
11. Subsidy एवं MSP (Minimum support price)
12. Research & Agricultural universities की स्थापना
13. Awareness, Education & training

Spectacular Rise in food grain Production in 3rd world country

Punjab v/s Bihar

Land reform failure

हरित क्रांति के चरण :-

Phase I - 1967-1980 :- यह पंजाब हरियाणा एवं प. उ. प्र. के कुछ भागों में केंद्रित रहा क्योकि नहर सिंचाई विकसित थे अतः HYV का प्रयोग संभव था।

1968 में देश के गेहूँ उत्पादन में कुल 2.5 गुना से अधिक वृद्धि पायी गयी। 1975 में CADP Progg. द्वारा Second thrust एवं IRDP के माध्यम से कृषि उत्पादकता एवं ग्रामीण विकास हरित क्रांति के प्रणोदक माने जा सकते हैं। परन्तु ये हरित क्रांति न होकर गेहूँ क्रांति माना जाता है परन्तु 1975 में भारत आत्मनिर्भर हुआ तथा खाद्य संकट से निवृत्ति हुई।

Phase II - 1980-1995 :- इस चरण में खरीफ फसल Ex - चावल एवं oil seed पर बल दिया गया तथा हरित क्रांति का विस्तार चावल उत्पादक राज्यों में किया गया। आंशिक सफलता KG delta, तमिलनाडु, Bengal delta में प्राप्त हुई। चावल की कुल उत्पादकता में 1.8 गुणा वृद्धि देखी गयी परन्तु Bihar, Assam, Orissa, E. UP में असफल रहा जिसका कारण राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव एवं लोगों के अंधविश्वास, अशिक्षा के कारण था। 1980-85 में oil seed development Prog. को भी आंशिक सफलता मिली। यह MP, Raj में सफल रहा किन्तु बुंदेलखण्ड, बघेलखण्ड, eG में असफल रहा।

Phase III - 1995-2002 :- Integrated water shed Managment prog. के माध्यम से G.R. का विस्तार शुष्क कृषि प्रदेश में किया गया जहाँ मूलतः ज्वार, बाजरा, रागी, कपास, दलहन तिलहन etc. पर बल दिया गया।

आंशिक सफलता । तिलहन के उत्पादन के द्वारा भारत के आर्थिक बजट की बड़ी मात्रा पर बचत संभव थी क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है तथा आयात में मौद्रिक घाटे प्रतिवर्ष बढ़ रहे थे।

Phase IV : Rainbow Revolution :- कृषि के बहुआयामी विकास की कल्पना
(2002 - 2007)

जिसमें श्वेत क्रांति (दुग्ध), नीली क्रांति (मत्स्य), silver क्रांति (Poultry), लाल क्रांति (मांस), Brown क्रांति (उर्वरक), Yellow क्रांति (तिलहन)

Rainbow rev. का उद्देश्य था हरित क्रांति का विविधीकरण, विस्तार, संपूर्ण क्रांति कृषि के अन्य सहायक कार्यों में वृद्धि रोजगार के अन्य साधनों का सृजन, कृषि औद्योगीकरण ग्रामीण विकास etc.

Ever Green Revolution :- 2007 - वर्तमान :- इसका अर्थ है कृषि का संपोषणीय विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि जो बिना भविष्य को संशय में रखकर। इसके अंतर्गत कृषि के सभी sectors का भविष्योन्मुखी विकास निर्धारित किया गया यह inclusive growth से भी प्रेरित है। इसके अंतर्गत second green rev. की बात की जा रही है जो आर्थिक विषमता को कम करें। कृषि का समेकित व संपोषणीय विकास हो एवं कृषि के अन्य आर्थिक क्रियाओं में भी क्रांति हो अतः Rainbow Rev. second green rev. का अंग है।

11th Five Year Plan से 2nd green revolution का प्रारंभ है।

THE BOOK SHOP
Shop No.- A-35/36, Bhandari House
Dr. Mukherjee Nagar Delhi-09
Phone ... 6552485

Case Study :- बिहार के पालीगंज में APJ Kalam के द्वारा आयुर्वेदिक फसलों व औषधियों का उत्पादन जो cash crop है।

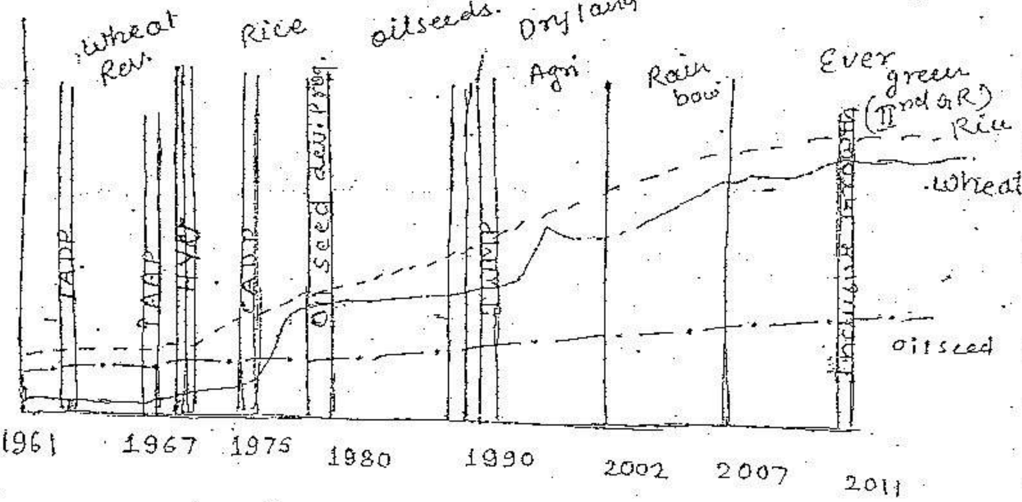

हरित क्रांति का प्रभाव :- आलोचनात्मक

गुण :- ① भारत की छवि विश्व में Bagging bowl की थी अतः अन्न क्रांति आवश्यक थी।

② भारत में खाद्य संकट से मुक्ति।

③ Self Reliance, Self sufficiency चतुर्थ योजना में प्राप्त।

④ दुर्भिक्ष कुपोषण, महामारी से मुक्ति।

⑤ भारत में खाद्यान्न के आयात में कमी इससे राष्ट्रीय धन की बचत जिसका प्रयोग सामाजिक अधिसंरचना में किया जा सकता है।

⑥ 1961 - 81 के मध्य भारत की जनसंख्या दो गुनी हो गयी इस प्रसंग में हरित क्रांति की महत्ता और भी बढ़ जाती है।

⑦ भारत में food security, कृषि का बाजारीकरण

⑧ कृषि आधारित उद्योगों का विकास

⑨ पहली बार पूँजीवादी कृषि एवं आधुनिक कृषि का निवेश।

10) ग्रामीण अधिसंरचनाओं का विकास।

11) कृषि के Forward एवं backward Linkage से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा।

12) तीव्र नगरीकरण की प्रक्रिया।

13) रोजगार सृजन।

14) PCI में वृद्धि, GDP, Per capita consumption तथा अन्य आर्थिक indicator बेहतर हुए तथा भारत विश्व में एक स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में उदित हुआ।

दोष :- आर्थिक :- ① प्रति व्यक्ति आर्थिक विषमता में वृद्धि

② Inter regional विषमता में वृद्धि। Ex- W. UP v/s E. UP.

③ Inter state dispairity. Ex- Punjab v/s Bihar

④ सामाजिक प्रभाव :- ① ग्रामीण भूमिहीनता
② ग्रामीण ऋणग्रस्तता

③ Marginal (सीमान्त) एवं छोटे किसानों का गरीब होना एवं नगरों की ओर पलायन तथा वे नगरीय श्रम बन गये।

④ – मशीनीकरण के कारण ग्रामीण शांति भंग हो गयी। Rural Tranquil

⑤ गाँव में प्रदूषण एवं शोर।

⑥ पूंजीवाद का उदय, वर्गविभेद

⑦ दहेज प्रथा, Status of women में गिरावट

⑧ सामाजिक कुरीतियों का प्रवेश

⑨ Rural handicapedness (ग्रामीण विकलांगता) → मशीन के प्रयोग में अज्ञानता

⑩ खालिस्तान की माँग (पंजाब में उग्रवाद का पनपना) अभिजात्य वर्ग का उदय

पर्यावरणीय प्रभाव :- ① प्रदूषण (जल, मृदा, वायु, ध्वनि)

~~② मृदा से~~

② मृदा से संबंधित प्रभाव → लवणीकरण विषाक्तीकरण एवं गहन कृषि क्षेत्रों में अम्लीयता का विकास, जल जमाव।

③ मृदा में Eutrophication..

④ जल से संबंधित → भौम जल का विनाश
→ भौम जल स्तर का निम्नीकरण
→ ट्यूब वेल के बहुधा प्रयोग से भौम जल के घटने के कारण पश्चिम समुद्री जल का रिक्त जलग्राहक चट्टानों में प्रवेश जिससे न सिर्फ लवणीकरण में वृद्धि बल्कि Land Pollution भी बढ़ा
→ Arsenic की मात्रा में वृद्धि।

⑤ कृषि पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव :- GR से crop monoculture किया गया जिससे मृदा से उस फसल के द्वारा प्रयोगित तत्वों का ह्रास।
→ कृषि विविधता का अंत।
→ अन्य पादप वर्गों को खरपतवार के रूप में विनष्ट किया गया।

आहार शृंखला तोड़ना

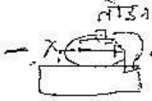

→ simplification
→ Co extinction
→ Bio invasion
→ Bio magnification
→ Eutrophication

जीवदशा के नष्ट;

→ Loss of biodiversity

→ Bio fragmentation
→ Deforestation
→ Choas Erosion

→ Locust invasion - (टिड्डा)

→ कीटनाशकों के अतिप्रयोग से नये पीढी के प्रतिरोधी कीटों का विकास हुआ जो पर्यावरणीय तंत्र में और भी दक्षता का ह्रास करते है।

दुर्भिक्ष (famine) - Paper 1

Class-9 old NCERT

Stress ↓ विनाश के पहले की दशा

Efficiency ↓ 1 tropic level से 2nd tropic level में energy Trans

परिभाषा - दुर्भिक्ष सामान्य अर्थ में खाद्य जल संकट है जो drought prone Region में आर्थिक एवं सामाजिक विभीषिका के रुप में प्राप्त होता है। दुर्भिक्ष एक सामाजिक आर्थिक दशा को दर्शाता है जिसमें कुपोषण, महामारी, अन्न जल संकट, अप्रवसन, पर्यावरणीय stress, सामाजिक तनाव एवं पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकता एवं दक्षता में ह्रास दिखता है।

दुर्भिक्ष पर अर्थशास्त्रीय विवेचना में यह कहा गया है कि यह एक आर्थिक संकट है। जब आर्थिक क्रियाओं में पूंजी निवेश का अभाव होता है। अतः कृषि एवं उद्योगों का slow down एवं अंततः आर्थिक संकट जैसी दशा परन्तु दुर्भिक्ष मानव जनित एवं प्राकृतिक दोनो कारकों से उत्पन्न होते हैं.

Meterological drought :- - - - - from old topi

Agricultural drought

Ecological drought :

Entitlement Theory :- अमर्त्य सेन ने इस संकल्पना में लिखा है कि प्रत्येक मानव जो अवतीर्ण होता है उसे संसाधनों के उस इकाई भाग पर प्राकृतिक अधिकार है जो उसके जीवन के संपोषणीय विकास एवं व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है।

इस मत के अनुसार दुर्भिक्ष मानव जनित संकट है जहाँ प्राकृतिक अधिकारों का छीन है।

→ दुर्भिक्ष पर मार्क्सवादी विचार में पूँजीवादी व्यवस्था का दोष माना गया है जहाँ धन का संकेन्द्रण चंद हाथों में होता है तथा Resource के ध्रुवीकरण व अतिदोहन के कारण दुर्भिक्ष की दशा बनती है अतः ये मानव जनित है।

→ दुर्भिक्ष का कारण :- ① प्राकृतिक कारण :-

ⓐ वर्षा का अभाव

ⓑ मरुभूमिकरण

ⓒ मृदा अपरदन

ⓓ प्राकृतिक संपदा का अभाव

② मानवीय कारण :- a) अधिक जनसंख्या

b) कृषि पर अधिक भार

c) औद्योगिक क्षेत्र का संविकसित होना।

d) माँग एवं आपूर्ति, विश्व में असंतुलन / विसंगति।

e) विश्व व्यापार में घाटा।

f) आर्थिक संकट।

परिणाम :- ① पारिस्थितिक :- a) मरुभूमिकरण

b) जैव विविधता का नाश

c) जल तंत्र का नाश

d) पारिस्थितिक तंत्र दक्षता एवं उत्पादन का ह्रास

② आर्थिक प्रभाव :-

③ <u>सामाजिक प्रभाव</u> :- कुपोषण, महामारी, civil war, अप्रवजन

<u>समाधान</u> :- UN के 3 Approach है :-

a) अन्न एवं खाद्य पेय पदार्थों का वितरण - immediate measure

b) मौद्रिक सहायता → अल्पकालिक उपाय

c) श्रम के लिए भुगतान → दीर्घकालिक उपाय

Shop No.- A-35/36,
Dr. Mukherjee Nagar
Phone :

06/09/2012

- Cropping Pattern
- Agri. productivity
- Cropping intensity

<u>कृषि प्रतिरूप / शस्य प्रतिरूप</u> :- शस्य प्रतिरूप से तात्पर्य मुख्य croping season Ex खरीफ (इसमें 80% भाग cultivated रहता है) किसी विशेष काल बिन्दु पर कृषि भूदृश्य की गणना अथवा अवलोकन है। कृषि प्रतिरूप मुख्य फसलों के व्याप्ति एवं उनके शस्य संयोजकता को प्रदर्शित करता है। यह एक स्थानिक विश्लेषण है इसमें मुख्य फसलों के क्षेत्रीय संकेन्द्रण, शस्य विविधता एवं शस्य संयोजन को दर्शाया जाता है।

Crop diversification (विविधता) का अर्थ है दिये गये कृषि क्षेत्र में सकल जोत भूमि पर फसलों की कुल संख्या

$$D = \frac{A}{n}$$

जहाँ A = Gross croped Area

n = No. of crops

Croping Pattern (शस्य प्रतिरूप) को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है :-

(1) <u>भौतिक कारक</u>

(i) <u>जलवायु</u> - (a) वर्षण
(b) तापमान
(c) आर्द्रता

(ii) मृदा :- (a) उर्वरता
(b) पोषकता
(c) संरचना एवं गठन

(iii) Hydrology
(iv) उच्चावच एवं ढाल
(v) ऊँचाई

② **गैर भौतिक कारक :-**

(i) सामाजिक कारक :- ⓐ कृषि परंपरा
ⓑ खान - पान

(ii) तकनीकी कारक

(iii) आधुनिक आगतों का प्रयोग :- ⓐ हरित क्रांति के 12 point

कृषि प्रतिरूप एक dynamic concept है जिसमें परिवर्तनशीलता स्थानिक एवं कालिक रूप में प्राप्त होती है। यह परिवर्तनशीलता प्रौद्योगिकी, आधुनिक आगतों के प्रयोग, सामाजिक क्रांति ~~एव~~ मांग एवं अन्य आर्थिक तथा dynamic कारकों का प्रतिफल होता है। ~~भारत में मुख्य~~

भारत में मुख्य फसलों का स्थानिक वितरण

① खरीफ season :-

Rg - Ragi

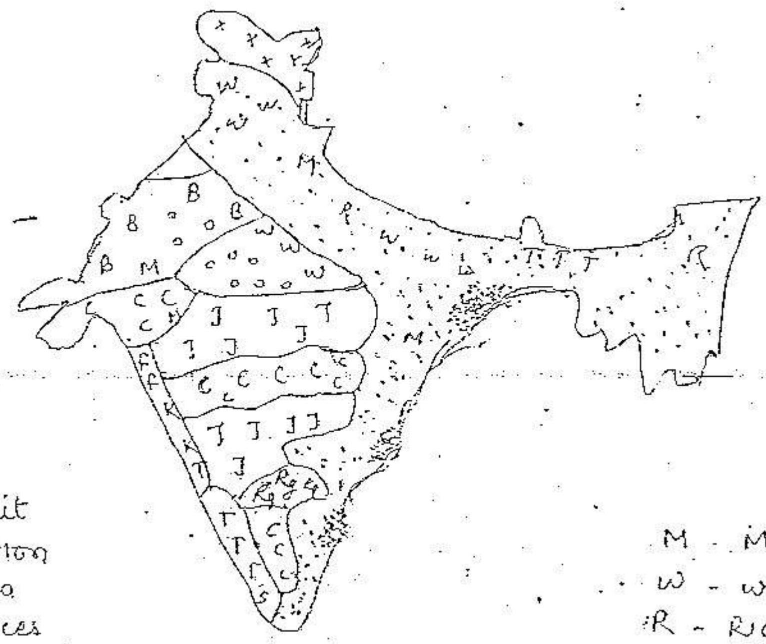

F - Fruit
C - cotton
T - Tea
S - spices
K -
B - Bajra

M - Maize
W - wheat
R - Rice
O - Oil seed
J - Jwar

100 cm. की रेखा भारत को आर्द्र कृषि एवं अनार्द्र शुष्क कृषि भागों में बाँटती है।

आर्द्र फसल :- चावल, चाय, मसाले

शुष्क फसल - ज्वार बाजरा, रागी, तिलहन

Cropping Patter की विधियाँ :-

a) Relative yield Index

b) Relative Dispersal Index

a) Relative yield Index :-

(प्रति Hect. उपज)

$$= \frac{\text{Avg. yield of crop } x \text{ for the total area}}{\text{Yield of crop } x \text{ for the given area}}$$

b) Relative dispersal Index

$$= \frac{\text{Total \% Acreage of crop } x \text{ in the total cultivated area}}{\text{\% acreage of crop } x \text{ for the given area}}$$

इसके आधार पर शस्य प्रतिरूप को 4 वर्ग में प्रदर्शित किया जाता है। जिसके 2 मुख्य आधार हैं :-

(1) Crop का yield

(2) ~~Total~~ % acreage / Dispersal :

(a) High yield High dispersal

(b) HYLD

(c) LY HD

(d) LY LD.

Rice :- यह एक खरीफ फसल है जो 100cm से अधिक वर्षा क्षेत्र जलोढ मृदा, water logging condn. उच्च T - 25-32°c की दशा में उत्पन्न होता है। यह एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। HYHD

THE BOOK SHOP
Shop No.- A-35/36, Bhandari House
Dr. Mukherjee Nagar Delhi-09

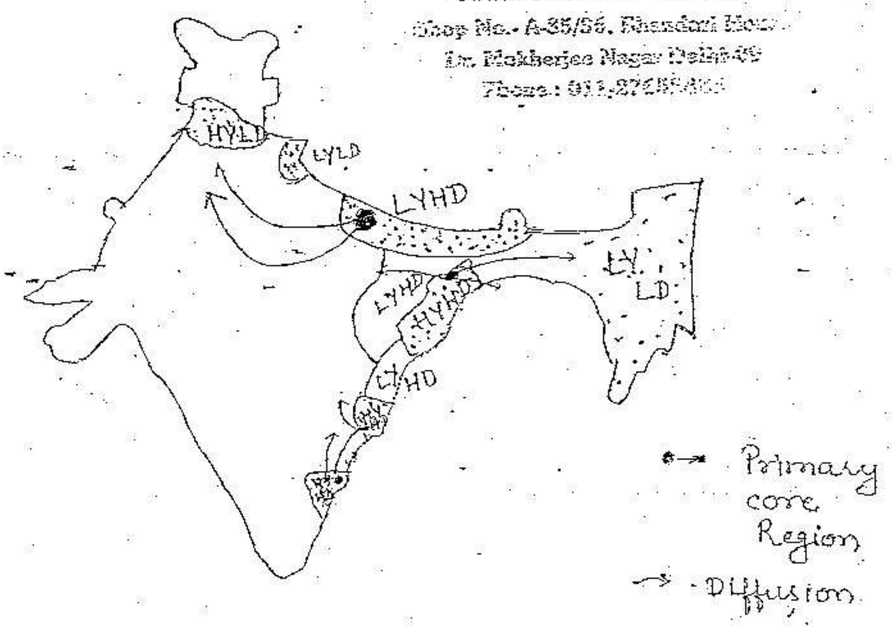

Agricultural Productivity :- कृषि उत्पादकता से तात्पर्य सामान्य अर्थ में प्रति Hectare उपज (yield) से है अर्थात दिये गये क्षेत्रफल पर कुल उपज को उत्पादकता कहते हैं परन्तु यह एक उचित परिभाषा नहीं है क्योंकि प्रत्येक फसल का output (निर्गत) एक ही जोत भूमि पर एक ही दशाओं में पृथक होता है।

कई विद्वानों ने उत्पादकता को अभिव्यक्त करने की कई विधियाँ प्रतिपादित की -

1) Input - output ratio (आगत - निर्गत अनुपात) :- इस विधि में कृषि के आधुनिक आगतों के प्रयोग के कुल मूल्य तथा कृषि उत्पादों के कुल मूल्य का आनुपातिक विश्लेषण किया जाता है। यह कृषि दक्षता को विश्लेषित करती है

6 कृषि दक्षता एवं उत्पादकता मे अंतर है हालांकि दोनो शब्द पर्यायवाची भी माने गये है। इस विधि का प्रयोग डा. खुसरो ने किया है। कृषि दक्षता का अर्थ है आधुनिक आगतों पर कुल व्यय से कुल निर्गत में कितनी वृद्धि होती है। कृषि उत्पादकता कुल योग को दर्शाती है अथवा ~~Aggregate~~ को, जो किसी भूमि पर प्राप्त होता है जबकि ~~कृषि~~ दक्षता में लागत - लाभ विश्लेषण निहित होता है।

Ex- Punjab में कृषि उत्पादकता में वृद्धि देखी जा रही है परन्तु कृषि दक्षता में कमी क्योंकि आगत cost में वृद्धि होने से लाभांश घट रहे है अतः कृषि दक्षता घट रही है

1970	100	500
2012	400	700

} उत्पादकता में वृद्धि but दक्षता में कमी

2) Per Hectare yield

3) कृषि पर प्राप्त कुल मौद्रिक लाभ :- यह विधि जसवीर सिंह ने प्रतिपादित की।

$$Productivity = (Y_i \times P_j) - c^t$$

Y_i = Total yield

P_j = मूल्य

i = एक चर है जो विभिन्न फसलों को दर्शाता है

j = एक चर है जो मूल्य के विविधता (variability) को दर्शाता है।

c = Cost (कुल लागत)

t = वह काल बिन्दु जिस पर कुल लागत का आंकलन किया जायेगा।

4) Dugley - stamp Method :- यह विधि दिये गये भूमि के द्वारा कुल जनसंख्या को संपोषित करने की क्षमता पर आधारित है जिसे carrying capacity of Land कहते है। इस विधि में दोष है क्योंकि पोषकता एक अनिर्वचनीय शब्द है।

Ex- उत्तर बिहार की सघन जनसंख्या के आधार पर उत्पादकता को उच्च नहीं माना जा सकता।

5) Ranking coefficient Method (कोटि गुणांक विधि) → Kendall

कृषि दक्षता को दर्शाने की सर्वोत्कृष्ट विधि मानी जाती है। इसमें प्रत्येक फसल के प्रति Hectare उपज की गणना की जाती है। दिये गये भू दृश्य को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जाता है तथा जिस कृषि प्रदेश की उत्पादकता का मापन करना है उस पर दिये गये फसलों के per hectare yield को गणित किया जाता है —

$$= \frac{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \ldots\ldots + R_n}{n \text{ (Total no. of crop)}}$$

$$= \frac{R_r + W_r + B_r}{n}$$

$$= \frac{C_{1r} + C_{2r} + C_{3r} + \ldots + C_{nr}}{n}$$

Ex- $\frac{1 + 1 + 4 + 20 + 3 + 2 + 5}{7} = \frac{36}{7} = 5.5$

index $\propto \frac{1}{\text{Productivity}}$

= 1 (श्रेष्ठ)

गुणांक विधि में यदि मान 1 से समीपस्थ है तो उत्पादकता उच्च होगी और यदि मान अधिक है तो उत्पादकता कम होगी। इस विधि के आधार पर भारत को 5 वर्गों में विभाजित करते हैं:

1.	Very high Productivity Region	< 75
2.	High Productivity Region	75-90
3.	Moderate Productivity Region	90-105
4.	Low Productivity Region	105-125
5.	Very Low Prod. Region	> 125

VHPR - पंजाब, उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी UP, गंगा यमुना दोआब, रोहिलखण्ड, शाहाबाद (Bihar), Lower bengal delta, Kaveri delta, Krishna-Godavari delta, Malabar के Kari प्रदेश, IG command area

कारण :- हरित क्रांति के 12 सूत्र

HPR :- मध्य गंगा का मैदान, दक्षिण भारतीय नदी घाटियाँ, उत्तर बंगाल, Assam plains

कारण :- शस्य गहनता का अधिक होना, उपजाऊ मिट्टी, आर्द्र जलवायु प्रदेश, 100 cm वर्षा, मृदा का नवीनीकरण, भूदा जल की उपलब्धता

समस्या :- जनसंख्या का बोझ

MPR :- जहां वर्षा 80-100 cm परन्तु सिंचाई की सुविधा पारंपरिक अथवा अनुपलब्ध है।
यह उपार्द्र क्षेत्र है। वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र है।
भूमि क्षमता कम है। मृदा की उत्पादकता सामान्य है।
कृषि वर्ष 4-6 महीने ही व्याप्त रहती है
मुख्य फसल - Cotton, ज्वार, रागी, मक्का, एवं कुछ सिंचित क्षेत्रों में जहां नदी घाटियाँ व्याप्त हैं वहां गेहूं का उत्पादन भी प्राप्त होता है।

गुजरात Plains, सौराष्ट्र, विदर्भ, खानदेश, बुंदेलखण्ड, बघेलखण्ड, उत्तरी तेलंगाना, कोंकण तट

LPR :- पूर्वी राजस्थान, पर्वतीय कृषि प्रदेश Ex- कश्मीर घाटी, दून घाटियाँ, शुष्क प्रायद्वीपीय पठार

VLPR :- पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश, North East India, लेह- लद्दाख प्रदेश

Cropping Intensity :- CI (शस्य गहनता) का सामान्य अर्थ है कि दिये गये कृषि वर्ष में कुल जोत भूमि पर कितनी बार विभिन्न फसल season में फसलों को बोया गया। cropping intensity भूमि उपयोग को दर्शाता है। परिभाषतः CI gross cultivated area (सकल जोत भूमि) एवं Net sown area (शुद्ध बोया गया क्षेत्र) का आनुपातिक संबंध है जिसे % मात्रा में अभिव्यक्त किया जाता है।

सकल बोया गया क्षेत्र का अर्थ है यदि कृषक के पास 100 एकड़ जमीन है जिसमें खरीफ फसल 90 एकड़ पर, रबी फसल 60 एकड़ पर Zaib फसल 30 एकड़ पर किया गया। यहां

सकल क्षेत्र = 90 + 60 + 30 है

जबकि Net sown area = 100 acre

इस प्रकार $CI = \frac{\text{Gross cropped area}}{\text{Net sown area}} \times 100$

$= \frac{180}{100} \times 100\% = 180\%$

इस प्रकार CI = 180%

जिसका अर्थ है किसान दिये गये कृषि वर्ष में अपने भूमि को 1.8 Times उपयोग में लाता है।

300% - maximum CI

3 गुना - - -

~~नेहा~~ CI - 100% से कम नही हो सकता

CI ∝ Productivity

$\frac{180}{90} \times 100 = 200\%$

$CI = \frac{90}{90} \times 100 = 100\%$

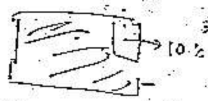

इस विधि के आधार पर भारत को 5 वर्गों में बांटा गया -

i) VHCI - 175% से अधिक

ii) HCI - 150 - 175 %

iii) MCI - 135 - 150 %

iv) LCI - 120 - 135 %

v) VLCI - < 120 %